[Shri Amar Nath Chawala]

on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 28th February, 1974."

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That this House do agree with the Thirty-sixth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 28th February, 1974."

The motion was adopted.

15.31 hrs.

RESOLUTION RE FREE AND FAIR ELECTIONS—*Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now we take up the further discussion of the Resolution moved by Shri Atal Bihari Vajpayee. Shri Atal Bihari Vajpayee to cotinue his speech.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : उपाध्यक्ष महोदय, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र के आधार है किन्तु यह खेद का विषय है कि भारत में चुनाव अधिकाधिक भ्रष्ट होते जा रहे हैं । प्रथम, भारत में चुनावों पर पूंजी का प्रभाव बढ़ रहा है । दूसरे, चुनावों में शासन तन्त्र का खुला दुरुपयोग होने लगा है । कानून के अन्तर्गत उम्मीदवारों के चुनाव व्यय पर रोक लगाई गई है, एक सीमा निर्धारित की गई है—यह सीमा लोक सभा के लिए 35 हजार रुपये तथा विधान सभा के लिए, कुछ अन्तर के साथ, 12 हजार रुपये है किन्तु सभी जानते हैं इस सीमा का पालन उल्लंघन में ही अधिक होता है । चुनावों में राजनीतिक दल जितना धन व्यय करना चाहे कर सकते हैं । मेरी पार्टी को छोड़ कर शायद ही कोई राजनीतिक दल ऐसा हो जो जनता के पास जाकर थोड़ा बहुत धन इकट्ठा करने का प्रयास करता है । किन्तु केवल उसके बलबूते नहीं चुनाव लड़ा जा सकता है । सभी दलों के अधिकांश उम्मीदवारों को चुनाव के लिए धन कुबेरों के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं । कम्पनियां कानून से राजनीतिक दलों को चन्दा नहीं दे सकती हैं लेकिन राजनीतिक दल धन एकत्र करते है। स्पष्ट है यह धन नं० 2 का होता है । इस धन का कोई हिसाब नहीं होता है ।

डाक्टर सेठी की गणना के अनुसार राष्ट्रपति, लोकसभा, विधान सभाओं आदि के चुनावों पर भारत में लगभग 100 करोड़ रुपया खर्च होता है । उनका कथन है कि अमरीका में होने वाले चुनाव व्यय की तुलना में यह खर्च ज्यादा है । आप यह स्वीकार करेंगे कि जो तत्व 100 करोड़ रुपया काला धन चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक दलों को देते है वे उसके बदले में स्वयं कितना काला धन बनाते होंगे, इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है ।

शासन तन्त्र के दुरुपयोग की घटनायें न केवल बढ़ती जा रही हैं, उसके स्वरूप में भी परिवर्तन हो रहा है । पिछले चुनावों के पश्चात् कई ऐसी चुनाव याचिकायें आई जिनमें ट्रिब्यूनल को, हाई कोर्ट को यह निर्णय देना पड़ा कि रिटर्निंग आफिसर उम्मीदवारों को अनुगृहीत करने के लिए मत-पत्रों में हेरा फेरी करते हैं, गलत तौर पर नामजदगी पर्चे रद्द कर देते हैं । श्री एस० पी० सेनवर्मा ने, जब वे मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ऊटी में यह बात कही थी कि अगर रिटर्निंग आफिसर निष्पक्षता से अपना कर्तव्य पालन नहीं करेंगे तो चुनावों को स्वतन्त्र नहीं रखा जा सकता है लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कानून में सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध केवल व्यक्तिशः रूप से कार्यवाही हो सकती है । अगर कोई उम्मीदवार किसी सरकारी कर्मचारी के प्रभाव का या उसके अधिकार का उपयोग अपने पक्ष में करें तो उसका चुनाव अवैध हो सकता है, सम्भवतः वह कर्मचारी भी दण्ड का अधिकारी बन सकता है लेकिन जहां संगठित रूप से सत्तारूढ़ दल मतदाताओं को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए या उन्हें भ्रष्ट करने के लिए शासन तन्त्र का दुरुपयोग करता है उसके विरुद्ध कानून में कोई प्रावधान नहीं है । इस दृष्टि से कानून बहुत ही सीमित है । मैं एक अंश उद्धृत करना चाहता हूं :

'The conditions obtaining procurement or abetting or attempting to obtain or procure any assistance for the furtherance of a candidate's election from any Government servant.'

लेकिन जहां सरकार का सारा ढांचा सत्तारूढ़ दल

की सहायता के लिए सक्रिय हो जाता है वहां चुनाव बराबरी की लड़ाई नहीं रहती । विपक्षी दलों को एक ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए विवश किया जाता है जिसमें वे गहरे प्रतिकूल वातावरण में संघर्ष करते है । इस सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है कि चुनाव मे मंत्रियों को वायु सेना के विमानों, हेलीकोप्टरों व अन्य वाहनों का उपयोग करने का अधिकार नही होना चाहिए । जो संयुक्त प्रवर समिति बनी थी, चुनाव कानून मे संशोधन करने के लिए उसने भी इस प्रश्न पर विचार किया लेकिन बहुमत की रिपोर्ट यह है कि सरकारी साधनो का दुरुपयोग राजनीति दलों मे मतैक्य से रोका जाना चाहिए, परम्परा विकसित की जानी चाहिए जिससे इस तरह के साधनों का दुरुपयोग न हो । सत्तारूढ दल कानून के द्वारा इस भ्रष्ट आचरण को रोकने के लिए तैयार नही है ।

चुनाव के दिनो मे प्रधान मंत्री दौरा करे इसमे किसी को आपत्ति नही हो सकतीहै । लेकिन प्रधान मंत्री अपना दौरा प्रधान मंत्री के नाते नही करती है, पार्टी की नेत्री के नाते दौरा करती है फिर कोई कारण नही है कि उन्हे वायुसेना के विमान उपलब्ध किये जाये, 4-4 हेलीकॉप्टर्स की कतार उनके साथ उड़े, पी० डब्ल्यू० डी० मचो की व्यवस्था करे और बैठने की व्यवस्था पुलिस के जिम्मे हो । अन्य दलो को यह सुविधाये उपलब्ध नही होती इससे अन्य दल बड़े घाटे मे रहते है । इतना ही नही, मुख्य मंत्री भी हेलीकॉप्टर मे उड़ने लगे हैं, अन्य मंत्री भी हवा मे उड़ते नजर आते है । कानपुर से उन्नाव जिसकी दूरी 13 मील है उसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री हेलीकोप्टर का प्रयोग करते थे । वहा पर उनको सुनने के लिए अधिक भीड़ भले ही न आये, हेलीकोप्टर को देखने के लिए जनता जरूर जमा हो जाती है । मेरा निवेदन है कि इस तरह के साधनो का दुरुपयोग जनता में एक आक्रोश की भावना पैदा कर रहा है, प्रतिपक्ष में असहायता का भाव जगा रहा है । उसके मन मे यह रोष उत्पन्न कर रहा है कि चुनाव की लड़ाई बराबर की लड़ाई नही है और जो दल एक बार सत्तारूढ़ हो गया वह सत्ता हाथ में बनाए रखने के लिए सब कुछ करेगा । जहां तक परम्परा को विकसित करने का सवाल है, सरकार ने ऐसी परम्परा का विकास करने के लिए क्या किया है ? क्या राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई गई क्या कोई सर्वसम्मत हल निकालने का प्रयत्न हुआ । शासन तंत्र का दुरुपयोग सारे चुनाव को विकृत कर रहा है ।

जहा तक चुनाव पर पूंजी के बढ़ते हुए प्रभाव का प्रश्न है, कोई दो राय नही हो सकती है कि वह नही होना चाहिये । वान्चू कमेटी ने भी इस सवाल की चर्चा की थी और वह जिस परिणाम पर पहुची उसको मै उद्धृत करना चाहता हूं :

"We are of the opinion that in our country also the Government should finance political parties. We recommend that reasonable grants-in-aid should be given by the Government to national political parties and suitable criteria should be evolved for recognising such parties and determining the extent of grant-in-aid to each of them. For according recognition to a political party for this purpose, it should be registered under the Societies Registration Act, 1860 and its yearly accounts are audited and published within a prescribed time. Irrespective of the decision of Government on the question of financing political parties, we recommend that the parties be required to get their accounts audited and published annually."

संयुक्त प्रवर समिति ने इस सुझाव पर विचार किया था कि चुनाव का अधिकाधिक खर्चा सरकार को वहन करना चाहिये और यह सिफारिश की थी उसने कि इसके लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की जाए । वह समिति क्यो गठित नही की गई ? क्या संयुक्त प्रवर समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें सरकार की अलमारियो की शोभा बढ़ाने के लिए होती है ? क्यों सरकार उनको गंभीरतापूर्वक नहीं लेती है ? समय आ गया है कि हम तय करें कि चुनाव का खर्चा कौन वहन करेगा । क्या उम्मीदवार करेगा या राजनीतिक दल करेगा या सरकार करेगी । इंग्लैंड के वे दिन राजनीति शास्त्र के

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

विद्यार्थियों को याद होंगे जब पोलिंग बूथ बनाने के लिए और बैलट बाक्स के लिए उम्मीदवार को अपनी जेब से पैसा देना पड़ता था। लेकिन वे दिन बीत गए। अब तो समस्त लोकतंत्रवादी देशों में यह प्रवृत्ति बलवती हो रही है कि चुनाव का खर्चा सरकार को वहन करना चाहिये। मैं और दलों की स्थिति नहीं जानता। हमारे लिए तो कोई ईमानदार आदमी, गरीब आदमी चुनाव में लड़ाना बड़ा मुश्किल है। वह जीतेगा या नहीं, यह तो बाद की बात है। इससे पहले हम को उससे पूछना पड़ता है कि वह कितना खर्चा कर सकता है—(इंटरप्शन) पार्टियों की चर्चा मैं पहले कर चुका हूं। अगर यह बोझा पार्टियों पर डाला जाएगा तो पार्टियां पूंजीपतियों के दरवाजे खट-खटाएंगी, राजनीति लक्ष्मी चेरी हो जाएगी, राजनीति धन कुबेरों की दासी बन जाएगी। फिर राजनीति जन कल्याण का साधन नहीं रह सकती है। फिर आप समाजवाद की चर्चा मत करिये।

कल प्रधान मंत्री ने राज्य सभा में इस संबंध में विचार व्यक्त किए थे। उन्होंने कहा था कि अगर सरकार खर्चा करे तो वह बहुत हो जाएगा। हमारा देश बड़ा है। हमारा देश बड़ा है तो यह आनन्द की बात है। हम सब से बड़े लोकतंत्र हैं तो यह अभिमान की बात है। फिर थोड़ा सा खर्चा अधिक हो जाएगा क्या इस कारण हम लोकतंत्र की जड़ों पर कुठाराघात होने देंगे?

हम लोगों ने हिसाब लगाया है। अगर लोक सभा के लिए जो 35000 की व्यय सीमा रखी गई है और विधान सभा के लिए 12000 की, तो उसके हिसाब से चौथे चुनाव में जो उम्मीदवार अपनी जमानतें बचाने में सफल हुए थे अगर उन्हें खर्चा दिया जाता तो लोक सभा के लिए पांच करोड़ और विधान सभाओं के लिए दस करोड़ के करीब सरकार का खर्चा होता। लोक सभा की 515 सीटें हैं। चौथे चुनाव में 2364 उम्मीदवार खड़े हुए। उन में से 1204 की जमानतें जब्त हो गईं। 1160 उम्मीदवार बचे। 35000 के हिसाब से अगर आप लगा लें तो कोई बड़ी रकम नहीं बनती। विधान सभाओं में 3453 सीटें हैं। उनके लिए 15472 उम्मीदवार खड़े हुए। लेकिन केवल आठ हजार उम्मीदवार जमानतें बचा पाए। उनको अगर हम कानून के द्वारा निर्धारित व्यय दें तो किसी भी स्थिति में दस करोड़ से अधिक खर्चा नहीं होता।

अभी भी हम चुनाव पर जो खर्चा कर रहे हैं वह 22 करोड़ के करीब आता है। इलेक्ट्रल रोल तैयार करने में 3.45 करोड़, पार्लिमेंटरी इलैक्शन पर 7.41 करोड़, असैम्बली इलैक्शन पर दस करोड़ खर्च होता है। ये इलैक्शन कमीशन के आंकड़े हैं और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के लिए पद्रह करोड़ और खर्च करना यह कोई महंगी चीज नहीं है। वस्तुतः लोकतंत्र एक खर्चीली प्रक्रिया है। जहां दल नहीं है, जहां एक व्यक्ति शासन करता है वहां चुनाव के खर्चे का सवाल ही नहीं है, जहां एक ही दल लड़ता है और दूसरे दल लड़ नहीं सकते हैं वहां भी खर्चा कम होता है। लेकिन हमने समझ बूझ कर संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है। हम मतदाताओं को निश्चित अवधि के बाद अपनी राय के द्वारा प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार देते हैं। लेकिन यह अधिकार पूंजी के द्वारा दूषित नहीं होना चाहिये, चुनाव की प्रक्रिया धन के द्वारा विकृत नहीं की जानी चाहिये।

कई पश्चिमी देशों और पश्चिमी जर्मनी की बात वांचू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में उद्धृत की है। मैं उसी को उद्धृत करना चाहता हूं :—

"In this connection, it may be pertinent to refer to the manner in which this problem has been tackled in countries like West Germany and Japan. In West Germany, political parties are financed by the Government on the basis of the votes polled by them at the preceding election. In Japan, Government finances the election expenses of the national parties on the basis of the size of the constituency and also gives financial assistance for research and party publicity."

अन्य देश अगर इस पद्धति का अवलम्बन कर सकते हैं तो कोई कारण नहीं है कि हमारे देश में यह प्रक्रिया न अपनाई जाए।

चुनाव कानून में एक और बुनियादी संशोधन करने की आवश्यकता है। संयुक्त प्रवर समिति ने इस पर भी विचार किया था। आजकल हमारे देश में जो पद्धति विद्यमान है मजोरिटी सिस्टम है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। जो भी घोड़ा सबसे पहले पहुंच जाता है वह विजय का पुरस्कार ले जाता है। उससे सूत भर भी पीछे रहने वाला घोड़ा किसी गिनती में नहीं आता। यह एंग्लो अमरीकन पद्धति है। दुनिया के अनेक देशों ने इस पद्धति को ठुकरा दिया है क्योंकि यह पद्धति बड़ी विचित्र है। कभी कभी ऐसा होता है कि जिसे तीस चालीस प्रतिशत मत मिलते हैं वह चुन कर चला जाता है। पिछले चुनाव में एक घटना ऐसी भी हो चुकी है कि एक क्षेत्र में ऐसा उम्मीदवार चुनाव जीत गया जिसका डिपाजिट भी जब्त हो गया लेकिन वह विजयी हो गया क्योंकि और उम्मीदवारों के वोट उससे कम थे। ऐसा उम्मीदवार किसी चुनाव क्षेत्र में बहुमत का प्रतिनिधि होने का दावा कैसे कर सकता है? इस पद्धति में एक जुआ है। थोड़ा सा मतदाताओं के मत के परिवर्तन होने से चुनाव परिणाम अत्यन्त विकृत हो जाते हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूं।

1952 में सत्तारूढ़ दल को लोक सभा के चुनावों में 44.99 परसेंट वोट, 1957 में 47.78 परसेंट, 1962 में 44.73 परसेंट, 1967 में 40.82 परसेंट और 1971 में 44 परसेंट वोट मिले, लेकिन उसको सीटें 70 परसेंट ज्यादा मिली।

प्रश्न केवल कांग्रेस पार्टी का नहीं है। हमारे कांग्रेसी मित्र यह न समझें कि यह पद्धति हरदम उन के ही पक्ष में चलेगी; यह उनके खिलाफ भी जा सकती है। मैं उस का भी उदाहरण दे सकता हूं। 1962 में तामिलनाडू में कांग्रेस को 45.26 परसेंट वोट मिले। उस के बदले में उसे 41 में से 30 सीटें मिलीं। 1967 में उस को मिलने वाले वोटों में 4 परसेंट की कमी हुई, लेकिन उस की सीटें 30 की जगह कुल 3 मिलीं। केवल 4 परसेंट वोट कम होने से सीटों में इतना अंतर हो गया।

दिल्ली का दूसरा उदाहरण है, जो सत्तारूढ़ दल को भी प्रभावित करता है और हम को भी प्रभावित करता है। दिल्ली में 1962 में सत्तारूढ़ दल को 50 फ़ीसदी वोट मिले, और वह सभी सीटें ले गया। 1967 में उस के वोट थोड़े से कम हुए—उस को 38 फीसदी वोट मिले, लेकिन उसको केवल एक सीट मिली, जब कि हम को छः सीटें मिलीं।

पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस को 41.1 परसेंट वोट मिले और युनाइटिड फ्रंट को 41.36 परसेंट, लेकिन वोट लगभग बराबर होते हुए भी कांग्रेस को सीटें कम मिलीं। 1969 में कांग्रेस के वोट थोड़े बढ़े—41.31 परसेंट हो गये, और युनाइटिड फ्रंट के वोट भी बढ़ कर 41.98 परसेंट हो गये, किन्तु कांग्रेस की सीटें घट कर 127 से 55 रह गईं।

अभी मैं ब्रिटेन के चुनावों के परिणामों का विश्लेषण कर रहा था, तो मुझे एक जगह ऐसा दिखाई दिया कि कनजरवेटिव पार्टी केवल 4 परसेंट वोटों पर हाउस आफ़ कामन्स का बहुमत खो बैठी और उस की स्थिति बहुत खराब हो गई। क्या यह चुनाव पद्धति सही है? क्या यह जन-भावनाओं का उचित प्रतिनिधित्व करती है? क्या इसे परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए? संयुक्त प्रवर समिति का सुझाव है कि इस मैजारिटी सिस्टम की जगह हमें लिस्ट सिस्टम अपनाना चाहिए। संयुक्त प्रवर समिति का सुझाव है कि उस पर विचार करना चाहिए।

श्री सतीश चन्द्र (बरेली): यह हमारा रीकमेंडेशन नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: मैं जानता हूं कि आप ने उस का विरोध किया और फिर यह तय हुआ कि विशेषज्ञ उस पर विचार करेंगे। संयुक्त प्रवर समिति ने सिफारिश की है कि इस मामले पर विशेषज्ञों को विचार करना चाहिए। वे विशेषज्ञ कौन तय करेगा?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी): आप।

श्री अटल विहारी वाजपेयी : हम तय करेंगे ? तो फिर चौधरी साहब इधर आ जायें और हम उधर चले जाते हैं।

केवल मतों और सीटों का ही प्रश्न नहीं है। लिस्ट सिस्टम से बहुत सी बुराइयों का निराकरण हो सकता है। उस को अपनाने से मतदाताओं में दल के प्रति निष्ठा बढ़ेगी, व्यक्ति के प्रति नहीं। बिरादरीवाद खत्म होगा। मतदाता अधिक जागरूक बनेंगे। संसदीय लोकतंत्र में दलों के ढांचे को मजबूत करना जरूरी है, और यह दलों के ढांचे को मजबूत करने की एक प्रक्रिया हो सकती है इस में कुछ कठिनाइयां भी हैं। कोई भी पद्धति सर्वथा निर्दोष नहीं हो सकती है। लकिन आज हम जिस पद्धति के अन्तर्गत चुनाव कर रहे हैं, वह सर्वथा दोषपूर्ण है। वह एक बिखराव पैदा कर रही है। उम्मीदवारों की फौज की फ़ौज खड़ी हो जाती है। चुनाव में मुद्दे स्पष्ट होकर सामने नहीं आते हैं। और सब से बुरी बात यह हो रही कि देश में राजनैतिक दलों, जो संसदीय लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है, का विकास जिस ढंग से होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है।

हमारे संविधान ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की जिम्मेदारी इलैक्शन कमीशन पर डाली है। संविधान के अंतर्गत इलैक्शन कमीशन कई सदस्यों का हो सकता है। लेकिन अभी तक वह एक सदस्यीय इलैक्शन कमीशन है। इलैक्शन कमीशन का काम बढ़ रहा है। मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। लोक सभा और विधान सभाओं के चुनाव अब अलग होने लगे हैं। कमीशन को क्वासी-जुडिशल फंक्शन्ज अर्द्ध-न्यायिक कार्य, भी करने पड़ते हैं—उसे राष्ट्रपति को डिस-क्वालिफ़िकेशन, अनर्हता, के बारे में सलाह देनी पड़ती है। इस लिए यह आवश्यक है कि कमीशन एक-सदस्यीय न हो कर बहु-सदस्यीय हो, जिससे केवल एक व्यक्ति पर सारे निर्णय लेने की जिम्मेदारी न आये, निर्णय मनमाने न हों, बल्कि वे ऐसे हों, जो जनता का अधिकाधिक आदर और समर्थन प्राप्त कर सकें।

चीफ़ इलैक्शन कमिशनर जिस तरह से नियुक्त किये जाते है, उस पद्धति में भी परिवर्तन होना चाहिए। संविधान के अनुसार चीफ़ इलैक्शन कमिश्नर को राष्ट्रपति नियुक्त करते है। राष्ट्रपति सरकार की सलाह से काम करते हैं और सरकार एक दल की सरकार है। वह नियुक्ति में दलीय दृष्टिकोण से सर्वथा अछूती नहीं रह सकती।

एक बड़ी विचित्र स्थिति है कि जो सरकार में ला सेक्रेटरी होते हैं, वह चीफ़ इलैक्शन कमिश्नर बन जाते है। चीफ़ इलैक्शन कमिशनर बनने के बाद वह ला कमीशन के मेम्बर बन जाते हैं। जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे, वह अब चीफ़ इलैक्शन कमिश्नर हो गये हैं। मैं किसी व्यक्ति पर उंगली नहीं उठा रहा हूं। इस प्रक्रिया से मेरा मतभेद है।

हम ने लोकायुक्त और लोकपाल के संबंध में जो विधेयक तैयार किया है, जिसे अभी संसद् की स्वीकृति मिलना बाकी है, उस में हम ने यह निर्णय लिया है कि लोकायुक्त और लोकपाल ऐसा व्यक्ति होगा, जिस की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, मगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस की सलाह से, और संसद् में अगर कोई मान्यताप्राप्त प्रतिपक्ष है, तो उस के दल के नेता की सलाह से, या विरोधी दल मिल कर जिस व्यक्ति को तय करेंगे, उस की सलाह से लोकायुक्त और लोकपाल नियुक्त किये जायेंगे। क्या चीफ़ इलैक्शन कमिशनर के बारे में यह तरीका नहीं अपनाया जा सकता है ? वह सरकार की कृपा पर क्यों निर्भर रहें ? इस संबंध में भी संशोधन की जरूरत है।

16 hrs.

संयुक्त प्रवर समिति ने यह भी सिफ़ारिश की थी कि रेडियो पर सभी दलों को चुनाव के समय अपनी बात कहने का अवसर मिलना चाहिए। लेकिन इस संबंध में भी न तो इलैक्शन कमीशन ने कोई पहल की है, और न सरकार ने कोई कदम उठाया है। 27 फरवरी को श्री गुजराल ने एक सवाल का जो जबाव दिया, मैं उसको सदन के सामने रखना चाहता हूं।

प्रश्न यह था :

"Whether any initiative was taken by the Union Government to allow the use of All India Radio by political parties for election publicity;

If so, the main features thereof."

और उत्तर यह दिया गया :

"Government would welcome any agreed arrangement on the question of allocation of time for political broadcast on sound and TV media. However, attempts made, in the past, by the Election Commission to obtain an all-party consensus on such an arrangement at the time of elections have not been successful so far."

यह बरसों पहले की बात है । उस के बाद चुनाव आयोग ने कोई प्रयत्न नहीं किया । जायंट सिलक्ट कमेटी की रिपोर्ट है कि सब दलों को समान समय मिलना चाहिए । इस आधार पर इलैक्शन कमीशन एक फ़ार्मूला बना सकता है और सरकार को उसे मानने के लिए मजबूर कर सकता है । लेकिन एलेक्शन कमिश्नर ने सारा अधिकार, वीटो का अधिकार सत्तारूढ़ दल को दे दिया । अगर सत्तारूढ़ दल समय बांटने के प्रश्न पर सहमत न हो तो किसी भी दल को रेडियो पर चुनाव के समय आने का मौका नहीं दिया जायगा । मैं सत्तारूढ दल की मनःस्थिति समझ सकता हूं । उन के लिए तो रेडियो 24 घंटे खुला हुआ है । प्रधान मंत्री चुनाव की सभा में भाषण करती हैं और प्रति दिन सवेरे से लेकर आधी रात तक वह भाषण रेडियो पर दोहराया जाता है । क्या चुनाव में और नेता भाषण नहीं करते ?

एक माननीय सदस्य : आप का भी दिया जाता है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : गलत बात है । एक भी भाषण नहीं दिया गया है चुनाव के दौरान । मौरार जी भाई दौरा करते थे । सार्वजनिक जीवन में उन का एक स्थान है । उन से किसी को मतभेद हो सकता है । चौधरी चरण सिंह पुराने मुख्य मंत्री रहे हैं । लेकिन केवल प्रधान मंत्री का भाषण आएगा, यह रेडियो का दुरुपयोग नहीं है ? टेलीविजन का भी कांग्रेस पार्टी ने अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में लाभ उठाने का प्रयत्न किया । यह टेलीविजन और रेडियो कोई कांग्रेस पार्टी की सम्पत्ति नहीं है । यह भारतीय जनता की गाढ़ी कमाई से चलने वाले प्रचार के साधन हैं । अगर सभी दलों को समान सुविधाएं नहीं मिल सकतीं तो यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बात करना बन्द कर दें ।

मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव बीत गया । मैं यह प्रस्ताव पहले ही लाया था मगर श्री रघुरमैया जी की कृपा के कारण यह उस समय नहीं आ सका । लेकिन मुझे कोई दुःख नहीं है । आज हम शांत चित्त से लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रख कर इस प्रस्ताव पर विचार करें । ऐसे कदम उठाने जरूरी हैं कि चुनाव निष्पक्ष हों, चुनाव स्वतंत्र हों किसी भी दल को केवल इसलिए कि वह सत्ता में है कोई अनुचित लाभ उठाने का अवसर नहीं मिलना चाहिए । इसी भावना से मैंने यह प्रस्ताव सदन के विचार के लिए पेश किया है । मैं आशा करता हूं कि जिस भावना से यह प्रस्ताव पेश किया गया है उसी भावना से इस पर विचार किया जाएगा । कुछ और मुद्दे होंगे तो मैं बाद में उन की चर्चा करूंगा ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Resolution moved:

"This House expresses concern over the growing influence of money-power and abuse of official machinery in elections and in order to ensure free and fair elections directs the Government that—

(i) recognised political parties be given election grants as recommended by the Wanchoo Committee;

(ii) recommendations of the Joint Committee on Amendments to Election Law regarding equal radio-time for recognised political parties, making of Election Commission a multi-member body, reducing voting age to 18 years, and examination by high-power Committee of feasibility of adopting List System, be implemented;

(iii) Ministers be prohibited from using official machinery such as air-

[Mr. Deputy Speaker].

crafts, helicopters, vehicles and other facilities except on terms of parity with other recognised political parties and

(iv) counting of votes be conducted booth-wise."

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna): I beg to move :

That in the resolution,—

after "money-power" *insert*—

"communalism, regionalism, castism and *other* disruptive activities" (1).

That in the resolution,—

add at the end—

"(v) measures be taken to ban communal, separatist, regional and caste-based propaganda by communal, reactionary and separatist parties and organisations in the interest of secularism, democracy and unity of the country ;

(vi) votes should be asked only on the basis of programmes and policies by the contesting parties and their candidates ; and

(vii) system of proportional representation should be adopted for the Parliamentary and Legislative Assemblies elections." (3).

SHRI BIBHUTI MISHRA (Motihari) : I beg to move :

That in the resolution,—

add at the end—

"(v) an impartial Commission be appointed to suggest the population for Lok Sabha and Vidhan Sabha constituencies and other measures for ensuring free and fair elections including the election expenditure being borne by the Government."(4)

MR. DEPUTY-SPEAKER : The Resolution and the amendments are before the House for discussion.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Burdwan) : We support this resolution. I wish Mr. Vajpayee had included something else also in this Resolution, namely, attempt should be made to see that the elections were not rigged in this country. What has been happening in the country in the name of elections in some parts of India is a matter of grave concern. If you want to maintain parliamentary democracy in this country these things should not be allowed to happen. Even during the recent elections serious allegations were made how the election machinery has been misused. What has happened in Madhubani ? Under what law a part of the country where elections are being held could be cut off from all railway connections ? How can one say that no body will be allowed to get inside the area and under what authority is this done ?

AN HON. MEMBER : Shortage of coal.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Was there shortage of coal only in Madhubani ? Secondly what has happened in Gaighata ? Mr. Samar Guha will no doubt narrate what has been experienced in that place

16.04 hrs.

[SHRI VASANT SATHE *in the Chair*]

What happened in Belgachia? I have got a telegram here that has been received from Orissa. It says : "Unfair practice in counting at Khurda, unauthorised congress people were allowed to enter the counting room and interfere in counting leading to chaos. Valid CPM votes invalidated, and the same counted as Congress votes with mala fide intentions. Utkal Congress votes were counted in favour of Congress. Returning Officer refused to accept petitions against such irregularity, pray intervention".

It is very candid. We are coming from West Bengal and we are not surprised. This *modus operandi* was utilized in West Bengal in a large scale in 1972. Now, of course, they are having it back. The people whom you have trained are acting against you in some places. That is why you lost in Tinsura. This is precisely what is happening elsewhere. The rebel Congressmen are winning the elections by adopting the same tactics, which they learnt

during the last elections. This is happening in Gaighata and Belgachia. Is this how you are thinking of boosting parliamentary democracy?

Then, a Government is restored just because the election is in the offing. A Government that never faced the Legislature for a day is restored to fight the election. Is this your attitude towards elections in this country? Now whatever you may say the people know very well that President's Rule in UP was revoked and a popular Ministry was installed just for the purpose of having the official machinery under their control before the elections in one of the most important States in the country. There are charges that the official machinery has been very duly and properly utilized by the ruling party.

Shri Vajpayee referred the Prime Minister's helicopter tour. Certainly her time is valuable. But in the background of the election campaign, the time of other party leaders is also equally important, because they have also to cover as many States as possible within a short time. Why should the leader of the ruling party, who happens to be the Prime Minister, be necessarily given a monopoly of the use of such facilities? Then the Government should provide equal facilities to the other parties. Some convention or rules should be laid down in this regard. Are you giving equal opportunity or equal facility to each political party or candidate to go to the people and express their views and solicit their support? Are they being placed in the same position? Merely because a candidate belongs to the ruling party, why should he get better opportunities? Is that your standard of free and fair elections in this country?

In the 1971 elections it was alleged that Defence Department quota jeeps were given to the ruling party for their use. Why is this being done? Kindly see how the official machinery is being abused. We know who arranges the rostrum during the tour of the Prime Minister. This matter assumes greater and greater importance because it is not something which affects only a particular part of the country. Wherever elections are being held, the official machinery is being abused by the ruling party taking advantage of its special position in the country. So, there is no chance of any free and fair elections being held. In any case, the suspicion is bound to be there.

I cannot go into all the points. Kindly see the new method of counting of votes that has been evolved. This has, of course. the blessings of the Election Commission. It has sometimes been suggested to the which has framed the rules. So far as this question is concerned, it came up before the Joint Committee. The Joint Committee considered that matter. I had the honour to be a Member of the Joint Committee and I quoted in my Minute of Dissent what the Chief Election Commissioner, Mr. Sundaram, in the Report of the Election Commission on the Fourth General Elections had said. He said:

> "The rules provide for the announcement of the result of counting in respect of each polling station separately. It has sometimes been suggested to the Commission that this method of counting naturally results in the political affiliation of small polling areas with about 1000 electors on an average becoming a matter of common knowledge. It is said that this leads to victimisation and harassment of particular areas which have voted strongly against the candidates of the party in power. The Commission doubts if this is true to any appreciable extent and is inclined to think that an odd instance here or there is being exaggerated to make out the prevalence of a reprehensible and undemocratic practice. The method of counting now in vogue has certainly the merit of being systematic which would be lost to some extent if, as suggested, the ballot papers found in a larger number of ballot boxes were first mixed up, put in bundles of 1000 or 2000 and then counted. Even on this pattern, it should not be difficult for the political parties,

if they were so minded, to find out broadly how a particular area voted."

Our contention is that by adopting a particular system of counting, an unreal situation is being created because the parties do not know what is their respective position in particular areas. So far as the plea of victimisation and harassment is concerned, there are other laws in the country which should be able to take care of it. But this rule has been adopted because through the means of this rule, unaccounted ballot papers which come from a particular booth, no body knows from which particular booth how many ballot papers are coming. No body knows in which area there has been any disorder or any unfair means adopted in a particular booth. We find that the whole counting system which has been adopted by the Election Commission with the blessings of the ruling party is directed towards creating a situation where the real state of affairs cannot be found out.

So far as the election expenses are concerned, I agree substantially with Mr. Atal Bihari Vajpayee that this has become a farce. The Joint Committee said that this has become a farce. Nobody knows how much actually has been spent although most of the Members seem to suggest that they have not exceeded the limit. But it was generally understood, generally believed, that almost large number of candidates have exceeded this limit.

What is the source from where the money comes? Even with the prohibition imposed on the companies by the Companies Act, the money comes from the corporate sources, from the business people, who do not account for it. This has been a good outlet for the black money which is allowed to be generated and to have an impact on the Indian economy because this black money finds its way to a particular source which will be used against for the purpose of elections. And the results of such elections are tainted with the use of black money.

These problems are not being tackled although I know these matters were gone into by the Joint Committee. A Bill has been brought forward but very important points have not been tackled by the Bill. That is a half-hearted measure.

I support the Resolution substantially and I submit that the most important point now about free and fair elections is that a a serious attempt is to be made to stop rigging of the elections. This has become an order of the day. There have been serious charges. When complaints are made, these are ignored on the plea that we have got the majority; we do not take note of them because we have got the votes somehow or other. These charges are not looked into.

During the Fourth General Elections, when I made complaints to the Chief Election Commissioner about some areas, he referred them to the district magistrate. My charges were against the district magistrate spearheading the machinery which was being mis-utilised for the purpose of rigging the elections. It was sent to the district magistrate against whom the charges were made. He said. "I did not make my mistake; I did not rig the elections." Then, the Chief Election Commissioner said that he had denied the charges and that he had nothing to do with it.

Wonderful inquiry: The person charged holds the inquiry and says, 'I am innocent'. This is a wonderful machinery! The Election Commission has become an impotent organisation for the purpose of going into this question. Nothing is done. The Election Commission has become an impotent countermand voting in particular booths as has been done in Gaighata in some of the booths, in West Bengal, and that he cannot countermand an election. This was Mr. Sen Varma's reply. He has no process or machinery to find out that an election in a particular constituency has been held fairly or not. Everybody does not like to go through the laborious process of filing election petitions which is not easy. It takes years for things to be decided.

The election petitions against many members in respect of the last elections are still pending. Nothing is being decided. What has happened to the election petition regarding Rae Bareli? It is still pending. The life of the Lok Sabha is about to be over. Therefore, Sir, one has to find out and set up a really independent and impartial machinary in which the candidates and the parties will have faith. The Election Commissioner sometimes tries to take up an attitude of impartiality, but we do not always agree with that. It is because there is no machinery to go into this question.

Therefore, I submit, these are very important matters. I am thankful to hon. Member, Shri Vajpayee, for having brought forward this Resolution, so that we can discuss this question. Government should take immediate steps to implement some of the suggestions which were accepted by Joint Committee.

श्री विभूति मिश्र (मोतिहारी) : चेयरमैन साहब, वाजपेयी जी इस प्रस्ताव को बडी विशुद्ध भावना से लाये होंगे, उन का भाषण भी बडा विशुद्ध हुआ। मैंने उस मे एक सशोधन भी दिया है, लेकिन एक बात मै जानना चाहता हू—पर उपदेश कुशल बहुतरे—हम दूसरे को शिक्षा दे, लेकिन पहले उस शिक्षा को अपने ऊपर भी तो ग्रहण करे। इन की पार्टी के साथ मैंने पाच चुनाव लड़े, हर दफा इन की पार्टी से लडने का मौका मिला। ये कहते है कि धन आता है—इन का इशारा दूसरी पार्टियो की तरफ़ था, यानी इन की पार्टी निष्पक्ष युद्धिष्ठिर जैसी है —नरोवा कुजरोवा—जैसी बात भी नही है।....

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह हमने नही कहा है।

श्री विभूति मिश्र : यह मै कह रहा हूं । आज अगर कोई पार्टी कम-व-बेश केडर-पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है, जिस मे ऐसे लोग है जिन का जीवन स्वाधीनता की लड़ाई में जेलो मे कटा है, जिन्होने जीवन में समाज और देश के लिये अनेको यातनाये सही है। कांग्रेस पार्टी में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो शुद्धता को निभाते है, लेकिन अपोजीशन पार्टियों में क्या है—कुछ में हैं, लेकिन अधिकतर ऐसे नही हैं।

वाजपेयी जी ने आज जो भाषण दिया है, वह बहुत शुद्ध है, मै उन के साथ हूं, चुनाव में 100 फीसदी शुद्धता आनी चाहिये, लेकिन प्रश्न यह है कि जिस पार्टी मे जो सदस्य हैं, वे कैसे सदस्य हैं, शुद्धता लाने का क्राइटेरिया क्या है। अगर किसी पार्टी के सदस्य ब्लैक-मार्केटियर हैं या दूसरे प्रकार के है, तो जैसे सदस्य होगे उस का रिफ-लेक्शन उस पार्टी पर पड़ेगा, ऐसी बात नही है कि उस पार्टी पर असर पड़ने वाला नही है । मैं वाजपेयी जी के साथ हू, वे बाल-ब्रह्मचारी है, यह शुद्धता निभाते होंगे, लेकिन मुझे बतलाईये, आप की पार्टी मे छोटे छोटे बनिये है या नही?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : किस पार्टी मे नही हैं, क्या आप के यहा नही है?

श्री विभूति मिश्र : मैं तो आप से पूछ रहा हू।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मै उस का जवाब दे रहा हू.

श्री विभूति मिश्र : आप को जवाब का मौका मिलेगा, तब दीजियेगा।

सभापति महोदय : लेकिन इस के साथ इन के बाल-ब्रह्मचारी होने का क्या सम्बन्ध है।

श्री विभूति मिश्र : मेरी पार्टी मे भी लोग है लेकिन इनकी पार्टी मे छोटे छोटे बनिये बहुत हैं। कहा से पैसा आता है, कौन पैसा देता है इनकी पार्टी को इसके लिए ही मैं ने कहा है कि कमीशन बनाया जाये और जांच की जाये। चुनाव मे इनकी पार्टी के पास कभी भी रिसोर्सेज की कमी नही रही है, कभी इनके पास पैम्फलेट्स की कमी नही रहती है। हमारे यहां बिहार मे चुनाव हुआ तो एक ऐसी पार्टी ने ऐसे पर्चे बम्ब मे छपवाकर लगवाये जो किसी तरह से हटने वाले नही थे। 1952 और 1957 के चुनाव मे मुझे

जीप नही मिली। इनकी पार्टी के लोग चुनाव में खड़े थे। 52 में मेरी इबल मेम्बर कांस्टीटुएन्सी थी और 57 में सिंगल मेम्बर फौरल कांस्टीटुएन्सी थी। आप इंक्वायरी करवालें अगर मैं किसी जगह भी जीप पर चढ़ कर गया होऊं। हां, रेल गाड़ी पर जरूर चढ़ा वरना साइकिल से चुनाव का दौरा किया। मेरे लिए इस उम्र में बिना गाड़ी के चुनाव लड़ना कैसे सम्भव होगा लेकिन अगर यह तय हो जाये कि कोई भी पार्टी सवारी नही रखेगी साइकिल मे चुनाव लड़ेगे तो ठीक है। (व्यवधान)

वाजपेयी जी ने प्रधान मंत्री जी के लिए कहा कि वे हवाई जहाज इस्तेमाल करती हैं तो इसके लिए कानून बना हुआ है, वे इस्तेमाल कर सकती है लेकिन इस्तेमाल करने के साथ साथ प्रधान मंत्री पैसा भी देती हैं। प्रधान मन्त्री जो हवाई जहाज या हेलिकाप्टर इस्तेमाल करती हैं उनके लिए हमारी पार्टी पैसा देती है। मैं आपको बताता हू हमारे यहा रामगढ के राजा ने जब चुनाव लड़ा तो सबसे पहले उन्होने हेलिकाप्टर का इस्तेमाल किया था। 5–7 मील की दूरी पर भी वे हेलिकाप्टर से जाते थे लेकिन फिर भी उनके आदमी हार गए। तो चुनाव से हेलिकाप्टर या हवाई जहाज ने नही जीता जाता है, चुनाव तो भावना से जीता जाता है। हमारी प्रधान मन्त्री ने जो चुनाव जीता है वह भावना से ही जीता है। त्याग, तपस्या और पार्टी के कैडर से चुनाव मे जीत होती है। पिछले साल प्रधान मन्त्री जी को किसी ने तलवार भेट की, किसी ने कुछ भेट किया बगला देश के सिलसिले मे और आज अगर फसल फेल हो गई, मंहगाई हो गई तो क्या उसकी वजह से लोग प्रधान मंत्री को भूल जायेगे? चुनाव में हार जाने की वजह से ही वाजपेयी जी इल्जाम लगा रहे हैं। हम चाहते हैं कि चुनाव अच्छे हो। विरोधी दल के एक बड़े आदमी ने 71 में मेरा विरोध किया। आप जानते हैं बिहार में थोड़ी बहुत जालपांति चलती है वैसे तो यह सारे देश में ही है। रिटर्निंग आफिसर से लेकर नीचे तक देखा गया मेरी बराबरी का कोई आदमी पोलिंग आफिसर, प्रेसाइडिंग आफिसर नही हुआ लेकिन गतलफहमी में, इसी जाति में जैसे कोई पांडे हैं, दूबे हैं और मैं मिश्र हूं, वह आ गए, हर तरह से मुझ को हराने की कोशिश की गई लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने मुझे वोट दिया और सारे आदमियों की जमानत जब्त हो गई। इसलिए मैं कहना हू आप जनतन्त्र की सेवा कीजिए। केरल में अपोजीशन पार्टी कोई नहीं है। शायद रामावतार जी की पार्टी है। एक भाई ने बगाल का उदाहरण दिया। मैं कहता हू इनके पास पैसा कहां से आता है? यह तो यह नोट फोर्ज करते है या फिर वह पैसा कही बाहर से आता है। चुनाव मे जीप वगैरह सभी कुछ इनके पास रहता है। चुनाव में इनकी जीपे कम नही घुमती है।

ऐसी हालत मे मैं चाहता हू कैडर बेस्ट पार्टीज हो। इसके होने से चुनाव मे खर्चा कम होगा। एक और बात है। यह जो जनसघ है इसके पास एक कैडर है आरएसएस। वह तो एक फौज है जो टूट पडती है बूथों पर कब्जा करने के लिए। वह कहने हैं जनसघ से कोई तालुक नही है लेकिन चुनाव में तालुक आ जाता है और वह गुरुजी का नाम लेकर टूट पडते है डाकुओं की तरह से। इसलिए आप पहले अपनी पार्टी को जनतात्रिक पार्टी बनायें तब हम भी आपकी बात मानेगे। हम तो दिल से चाहते है कि हिन्दुस्तान में डिमोक्रेसी पनपे। हम इस बात को मानते है कि इसमें कुछ खराबी आ गई है लेकिन वह खराबी आपकी वजह से ही आई है। हम चाहते है सभी पार्टीज मिलकर बैठे और इस खराबी को दूर करने का यत्न करें ताकि इस देश में जनतन्त्र ठीक से चले। जबतक यहां पर जनतन्त्र शुद्ध नहीं होगा तबतक इस देश का कल्याण नहीं होगा। 71 मे जब हम चुनाव लड़े तो बिहार में कर्पूरी ठाकुर की गवर्नमेन्ट थी जिसमें वाजपेयी जी भी शामिल थे इनके लाख बाधा देने के बाद भी लोकसभा में काफी तादाद मे इन जीत कर आये क्योकि जनता समझती थी हमारी पार्टी से ही उनका कल्याण होने वाला है। कुछ सूखा पड़ गया, फसल मारी गई तो जनता को रंज हो गया लेकिन भाई भाई में लड़ाई होती है, इसको भी

हम सुधार लेंगे और फिर जनता हमारे साथ हो जायेगी। हम चाहते हैं किसी भी पार्टी को चुनावों में यह कहने का मौका न मिले कि चुनाव अनफेयर मीन्स से हुए। हमारे ला मिनिस्टर यहां बैठे हैं, मैं चाहता हूं ऊपर से लेकर नीचे तक एक इन्डेपेन्डेन्ट कमीशन बनाया जाये। स्टेट गवर्नमेन्ट में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रिटर्निंग आफिसर होता है और एस०डी०ओ० असेम्बली में असेम्बली के लिए रिटर्निंग आफिसर होता है। लेकिन मैं चाहता हूं ऊपर से लेकर नीचे तक एक बिल्कुल इन्डेपेन्डेन्ट बाडी हो जोकि ठीक से चुनाव करवाये और उसका राजनीति मे कोई सम्बन्ध ही न रहे। किसी पार्टी की सरकार हो, उसका राजनीति से कोई समबन्ध न रहे चुनावों में हम शुद्धता चाहते लेकिन यह तभी सम्भव है जबकि समाज में हम सुधार लायें। लाख हम कानून बनायें लेकिन अगर समाज में सुधार नही लायेंगे तो फिर कैसे होगा ? मैं समझता हूं वाजपेयी जी का प्रस्ताव बहुत शुद्ध है लेकिन इस प्रस्ताव के ऊपर वे खुद अमल करे तो बहुत अच्छा होगा।

इसके अलावा प्रधान मंत्री जी के लिए जो कहा गया, मैं कहता हूं चुनाव की बात छोड़ दीजिए, यों भी आप इस बात को मानते है कि कि उन्होंने और उनके खानदान ने कितना त्याग किया है, वे तो जहां भी जायेंगी लोग आप से आप यहां आयेंगे। आप इसको रोक नही सकते है। यदि आप भी उसी तरह से त्याग और तपस्या करें तो आपकी भी कुछ हो सकती है। जब बंगला देश का मामला था तो आप कहते थे कब लड़ाई होगी लेकिन आपने देखा लड़ाई हुई, अमरीका का सातवां बेड़ा भी आ गया लेकिन उनके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं आई। आप सब ने साथ दिया। अमरीका से गल्ला मंगाते थे। हमारे कुछ विरोधी भाई हमें इसके लिए गाली देते थे कि क्यों मंगाते हो। आज हमने गल्ला मंगाना बन्द कर दिया है। उसकी कमी भी है। लेकिन कोई भूख से मरा नहीं। थोड़ा सा कहते तो पैदा हो गया है लेकिन कोई भूख से मरा नहीं है। दिक्कत तो बहुत हो गई है। पैसा बहुत बढ़ गया है। लेकिन कोई भूखा नहीं मरा।

ब्लैक के पैसे की बात उन्होंने की है। हमें तो ब्लैक का पैसा आज तक किसी से नहीं दिया। अपोजीशन के श्री श्याम बाबू ने मेरे बारे में कहा था कि 1952 के चुनाव में पांच आने या सवा रुपया खर्च करके जीत गए थे। जो ब्लैक का पैसा लेते हैं वही जाने। शायद उनको इसकी जानकारी होगी ? हमको जानकारी नहीं है कि कहां से वह आता है। और कहां जाता है। उनकी पार्टी की लिस्टों को देखा जाए तो उस में शायद आपको ब्लैक वाले मिलेंगे। छोटे से छोटा बनिया जो है यही गड़बड़ करता है। ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिये।

मैं यह भी चाहता हूं कि हमारे देश में दो तीन पार्टियां हों। दस दस आदमियों की यहां पार्टियां हो जाती है। कोई इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाता है।

चुनाव फेयर हों इसका ध्यान सब को रखना चाहिये। अगर ऐसा नही होता है तो डैमोक्रेसी खतरे में है। गलत तरीके से सरकार पर कब्जा करने की कोशिश नहीं होनी चाहिये।

पार्लिमेंट्री इलेक्शन के लिए आपने 35000 और विधान सभा के चुनाव के लिए 12000 की लिमिट लगा रखी है। हमारे विरोधी दल के माननीय सदस्य श्री वाजपेयी जी ने खुद कबूल किया है कि इस लिमिट से ज्यादा पैसा खर्च लोगों ने किया है। मैं चाहता हूं कि वह कानून का पालन करें। गांधी जी के पदचिन्हों पर चलें। उनको उदाहरण पेश करना चाहिये था मेम्बरी से इस्तीफा दे कर और बिना खर्च के चुनाव जीत कर आना चाहिये। एक पार्टी के ज्यादा लोग जीत सकते हैं तो दूसरी के भी ज्यादा जीत सकते हैं। आप ज्यादा झंडे रख सकते हैं तो दूसरा भी ज्यादा रख सकता है। पीले कागज पर जितना खर्च आपका एक झंडा बनाने पर आता है उससे हमारा पांच गुना ज्यादा पैसा उस पर लग जाता है। आप तो विदेशी कपड़े पर भी अपना झंडा लगा सकते हैं। लेकिन हमारे यहां जो झंडा है वह हाथ से कते हुए कपड़े पर होता है, हाथ से बने हुए सूत के कपड़े पर होता है।

चुनाव में ज्यादा खर्चा न हो इसके वास्ते कड़े मैजर्स लेने चाहिये। उन्होंने जो-आक्षेप अपने भाषण में किए हैं उनको मैं नहीं मानता। उससे कोई लाभ नहीं है। चुनाव शुद्धता से हों, प्रजातंत्र शुद्धता से चले इसके लिए हम सब को प्रयत्न करने चाहिये। आपकी सरकार बिहार में बनी थी, संविद सरकार वहां 1971 में बनी थी। उसके कारनामों को आप देखें। चुनावों में हम लोगों के प्रति उनकी क्या भावनायें थी इसको आप देखें। मैं चाहता हूं कि चुनाव किस तरह से शुद्धता से हो सकते हैं इसके लिए एक कमीशन की बहाली होनी चाहिये।

आज 8–9 लाख आदमियों के पीछे लोक सभा की एक कांस्टिट्युएंसी और डेढ़ लाख के पीछे विधान सभा की एक कांस्टिट्युएंसी होती है। इतनी बड़ी कांस्टिट्युएंसी में चुनाव लड़ने के लिए आप ही बताएं कैसे कोई पैदल जा सकता है और सवारी से भी जाए तो उसको कितना समय लग सकता है। पैदल जाने में कितने बरस लगेंगे? क्या वह सारे गावों को कवर कर सकता है? इतनी बड़ी कांस्टिट्युएंसी में अगर केडरलैस पार्टी होगी तो इतने बड़े क्षेत्र में चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाएगा। केडरलेस पार्टी बननी है तो चुनाव क्षेत्र को छोटा करना होगा।

जहां तक कुरप्शन का सम्बन्ध है उसका अन्त केवल बातें करने से नहीं होगा। उसके लिए जनता का करेक्टर ऊंचा हम को करना होगा। जनतंत्र में हमारी आस्था सुदृढ़ होनी चाहिये। जब तक यह नहीं होता तब तक कुछ नहीं होगा।

श्री रामावतार शास्त्री : (पटना) . इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं अपने संशोधन पेश करता हूं। इनकी आवश्यकता इसलिए पड़ गई कि वाजपेयी जी का प्रस्ताव अधूरा है। उनकी इस मांग का मैं समर्थन करता हूं कि मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवारों का जो चुनाव खर्चा होता है उसको सरकार को वहन करना चाहिये। ऐसा करने से चुनाव में जो कुछ गलत प्रक्रिया इस्तेमाल में लाई जाती है, भ्रष्टाचार होता है वह बन्द होगा।

देश में यह मांग जोरों से उठ रही है कि नौजवान जो अठारह बरस के हो चुके हैं उनको इस जनतंत्रीय युग में मतदान का अधिकार मिलना चाहिये। दुनिया के प्रायः सभी देशों में नौजवानों को जिन की आयु 18 बरस है मतदान का अधिकार प्राप्त है। समाजवादी देशों में सभी जगह है और ब्रिटेन, बंगला देश, अमरीका आदि में भी है।

इन्होंने चुनावों के नाम पर अधिकारों का जो दुरुपयोग होता है, सरकारी साधनों का दुरुपयोग होता है उस पर भी रोक लगाने की बात कही है। यह बहुत सही मांग है। मिश्र जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं। उन्हें अपना पिता जैसा मानता हूं। लेकिन उनके दल के लोग क्या करते हैं यह भी उनको मालूम है, भले ही वह इस तरह के काम न करते हों। वाजपेयी जी के दल के लोग भी क्या करते हैं, कांगो के लोग भी क्या करते हैं, स्वतंत्र पार्टी के लोग भी क्या करते हैं, जो पैसे वालों की मर्जी पर अपनी नीतियां तय करते हैं, वैसे दल क्या करते हैं यह सब को मालूम है। मैं एक ताजा उदाहरण देना चाहता हूं। मधुबनी में चुनाव हुआ। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का बहुत ढोल पीटा गया। शासक दल के लोग इसका बहुत ढोल पीटते हैं कि हमारा इतना बड़ा जनतंत्र है, देखो हम क्या करते हैं। ऐसा कहा गया लेकिन, आप देखें कि मधुबनी में 30 बूथ पर कब्जा कर लिया गया और गुंडों से ऐसा करवाया गया। यह किस ने किया? बिहार विधान सभा में विरोधी दल के नेता श्री सुनील मुखर्जी, जो कम्युनिस्ट पार्टी के भी नेता उन्होंने खुलेआम यह आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाया है। दूसरी बात यह है कि मधुबनी में रेलों को आप ने बन्द कर दिया जिसकी चर्चा हमारे मार्क्सवादी पार्टी के साथी ने की है। आज के अखबारों में इसका खंडन निकला है और श्री कुरेशी, रेल उपमंत्री कहते हैं कि चुनाव की वजह से नहीं बल्कि कोयले की कमी की वजह से ऐसा किया गया। श्री कुरेशी ने इतने दिनों के बाद यह बयान दे कर इसका खंडन किया है। जो गलत है।

आप देखें कि पटना से निकलने वाला सर्चलाइट क्या कहता है। यह बिहार का अखबार है,

कम्यूनिस्ट पार्टी का अखबार नहीं है : यह पी० टी० आई० जैसी सम्मानित समाचार एजेन्सी की खबर है ।

"Rail services to Madhubani cancelled.

"Madhubani, Feb. 23—PTI; All the passenger trains on the Sakri-Jaynagar section of the North-Eastern Railway were cancelled today and a notice to this effect was hung up on the notice board of the Madhubani Railway Station by the Station Master.

"No Up and Down trains are passing through Madhubani which is in this section. Madhubani goes to polls tomorrow.

"State buses are also not plying in Madhubani since morning while private cars, jeeps and trucks are engaged for election purposes.

'No reason has been given for the sudden termination of bus and train services. Informed circles believe that this step has been taken to prevent outside elements and students from coming to Madhubani to interfere with the elections."

क्या यही इस सरकार और सत्तारूढ़ दल की डेमोक्रेसी और जनतंत्र है ? रेल मंत्री को किस ने यह अधिकार दिया ? क्या उन्होंने ऐसा मंत्रि-मंडल के आदेश से किया ? क्या उन्होंने इस के लिए प्रधान मंत्री की इजाजत ली थी ? क्या ऐसे रेल मंत्री को अपने पद पर रहना चाहिए ? यह बड़े शर्म की बात है । उन से यह पूछा जाना चाहिए कि किसने उन्हें यह अधिकार दिया । उन से सफ़ाई मांगी जानी चाहिए । उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है अगर उन में सचमुच कुछ हया है, तो उन को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए । यह है कांग्रेस का उदाहरण ।

इसी तरह संगठन कांग्रेस ने 1971 के चुनाव में बेगुसराय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार श्री योगेन्द्र शर्मा को हराने के लिए कामदेव सिंह को इस्तेमाल किया, जो नाटोरियस और नामी गुंडा है, जो डिक्लेयर्ड एबस्कांडर है, जिस के लिए बरसों से दस हजार रुपये का इनाम रखा हुआ है और जो मशीनगन ले कर अपने दल-बल के साथ घूमता है । उस समय के मुख्य मंत्री, श्री कर्पूरी ठाकुर ने उस से गुप्त रूप में भेंट की और कहा कि जैसे भी हो, तुम श्री श्यामनंदन मिश्र को, जो संगठन कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जिताओ, सी० पी० आई० के कैंडीडेट को हराओ, तुम्हारे खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी । श्री योगेन्द्र शर्मा पांच एसेम्बली कांस्टीट्युएन्सीज में बीस हजार वोट से लीड कर रहे थे । कामदेव सिंह ने बेगुसराय की एसेम्बली कांस्टीट्युएन्सी में अपने दल-बल के साथ, मशीनगन के बल पर, पचास जनता ... पर कब्जा कर लिया । परिणाम यह हुआ कि श्री योगेन्द्र शर्मा की लीड भी खत्म हो गई और वह पांच हजार वोट से हार गये ।

उसी कामदेव सिंह को कांग्रेस ने मधुबनी में इस्तेमाल किया । उस ने पड़ोस में हमारे बूथों पर कब्जा कर लिया और वोटरों को डरा कर भगा दिया ।

कांग्रेस भी इस प्रकार की प्रवृत्तियों से अछूती नहीं है । वह भी ऐसे काम करती है और जनसंघ, ... भी करते है । स्वतन्त्र पार्टी का वहां कोई असर नहीं है । अगर उस को मौका मिलता, तो वह भी करती ।

श्री ओंकार लाल बेरवा (कोटा) : कम्युनिस्ट भी यही करते हैं ।

श्री रामावतार शास्त्री : चुनावों में सरकारी गाड़ियों का कितना इस्तेमाल किया जाता है, इसका तो कोई हिसाब ही नहीं है । 1957 में मैं पैदल जाया करता था । सरकार को यह नियम बनाना चाहिए कि सब उम्मीदवार पैदल चलें । तब हम समझेंगे कि सरकार और कांग्रेस इलैक्शन को पैसे के प्रभाव से मुक्त रखना चाहते है । पूरा देश जानता है कि कांग्रेस के पास पैसा कहां से आता है । अगर इस तरह की बातें होती रहेंगी, अगर

गुंडा दल बूथों और मत-पेटियों पर कब्जा करेंगे, पैसे के बल पर वोटरों को खरीदा जायेगा और जात-पांत, फ़िरकापरस्ती और हिन्दू या मुसलमान के नाम पर वोट मांगे जायेंगे, तो इस देश में चुनाव एक मजाक बन कर रह जायेंगे और जनतंत्र का भविष्य अन्धकारमय हो जायेगा।

आज सुबह प्रधान मंत्री ने ठीक ही कहा है कि सभी दलों को अपने कार्यक्रम और अपनी नीतियों के आधार पर वोट मांगने चाहिएं। तब जो समाजवाद में विश्वास करेगा, वह समाजवादी दल या कम्युनिस्ट पार्टी को वोट देगा और जो पूंजीवाद में विश्वास करेगा, वह वोट देने के लिए कांग्रेस, जनसंघ, कांगो और स्वतंत्र पार्टी में से किसी एक को चुनेगा। लेकिन आज क्या होता है ? वोट मांगने के लिए जात-पांत का इस्तेमाल किया जाता है और साम्प्रदायिक भावनाओं की अपील की जाती है। भारतीय क्रांति दल, मुस्लिम लीग, जनसंघ और आर० एस० एस० ने यू० पी० में क्या किया ?

श्री ओंकार लाल बेरवा : वही किया, जो कम्युनिस्ट करते है।

श्री रामावतार शास्त्री : शिवसेना क्या करती है ? कांग्रेस जनतंत्र की बात करती है। क्या उस को बम्बई में शिव सेना के साथ दोस्ती करते हुए शर्म नहीं आई ? लेकिन जनता ने उस को उचित जवाब दिया। कांग्रेस शिव सेना जैसी जनता की दुश्मन, हिन्दुस्तान की एकता को तोड़ने वाली और गैर-महाराष्ट्रीयों पर जुल्म करने वाली जमात को इस लिए जिन्दा रखना चाहती है कि उस का फ़ौरी स्वार्थ सिद्ध होता है। उस ने कम्युनिस्ट उम्मीदवार को हराने के लिए उस जमात के साथ समझौता किया, लेकिन उस को लेने के देने पड़ गये।

श्री विभूति मिश्र ने स्वयं आर० एस० एस० के बारे में कहा है। इस लिए मैं उस के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि हमारे सूबे में जातिवाद कम है। लेकिन मैं समझता हूं कि वहां जातिवाद की बीमारी सब से ज्यादा है और वह वहां पहले उभरी है। वह बीमारी यू० पी० में भी आ गई है। जातिवाद का इस्तेमाल करके और पिछड़ी जातियों तथा ऊंची जातियों का सवाल उठा कर, वहां बी० के० डी० ने लगभग 106 सीटें प्राप्त कर ली हैं।

अगर हमारे देश में ऊंची जाति और नीची जाति, हरिजन और गैर-हरिजन, मुसलमान और गैर-मुस्लिम, महाराष्ट्रीय और गैर-महाराष्ट्रीय, लक्षित सेना, बंगाली और गैर-बंगाली जैसी बातें चलेंगी, तो हमारी एकता टूटेगी, हमारा देश कमजोर बनेगा और उस के साथ हमारा जनतंत्र भी कमजोर हो जायेगा। मैं ने अपने संशोधनों के जरिये यही बातें कही हैं। पता नहीं, श्री वाजपेयी ने इन बातों को कैसे छोड़ दिया है। उन्हें इन बातों का भी जिक्र करना चाहिए था, क्योंकि इस तरह की शक्तियां हमारी एकता को तोड़ रही हैं, हमारे जनतंत्र को कमजोर कर रही हैं, उस को कुरेद रही हैं।

मैं एक उदाहरण दे दूं। सन् 1971 के चुनाव में मेरे खिलाफ जनसंघ के एक बड़े तगड़े उम्मीदवार थे। वह एक जाति-विशेष के थे। अपनी जाति में वह कहते थे कि मैं तुम्हारी जाति का हूं, मुझे वोट दो। और दूसरी जाति में जा कर वह कहते थे कि मैं ब्राह्मण हूं, मुझे वोट दो। वह कभी भूमिहार और कभी ब्राह्मण बन जाते थे। उन के समर्थक मेरी सात मतदान केन्द्रों की मत पेटियों को उठा कर ले गये। जब वहां दोबारा पोलिंग हुआ, तो उन बूथों पर मैं ने लीड किया।

इस तरह के गुंडा दलों पर बैन लगाया जाये। आर० एस० एस० और शिव सेना पर बैन लगाया जाये। मुस्लिम लीग को न पनपने दिया जाये। लक्षित सेना जैसी सेनाओं पर बैन लगाया जाये। तब हम समझेंगे कि यह सरकार और कांग्रेस स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के हामी हैं।

राजनैतिक दलों और उनके उम्मीदवारों को अपने अपने कार्यक्रम के आधार पर वोट मांगने का संवैधानिक अधिकार है। वे अपनी अपनी नीतियों को बतायें, ताकि जनता का दिमाग शिक्षित

हो और वह समझे कि जनतांत्रिक समाज में उस के क्या अधिकार और कर्तव्य हैं। जनता को बताया जाना चाहिए कि कौन पार्टी क्या करेगी। यह तो होता नहीं है, लेकिन जाति और वर्ग के नाम पर वोट मांगे जाते हैं।

श्री वाजपेयी ने बड़े विस्तार के साथ बताया है कि अल्पमत ले कर शासक दल सत्तारूढ़ हो जाते हैं और आम तौर से यही हो रहा है। आम तौर से 50 फीसदी से कम वोट आप को मिला है और आप चुन कर चले गए हैं। होना चाहिए प्रोपोर्शनल रेप्रेजन्टेशन-सानुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत माना चाहिए। पता नहीं वाजपेयी जी ने इस बात को क्यों छोड़ दिया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वह लिस्ट सिस्टम में आ जायेगा। लिस्ट सिस्टम का अर्थ ही वह है।

श्री रामावतार शास्त्री : क्यों कि जिस के जिस अनुपात में वोट आएगे उस को उस अनुपात में स्थान होना चाहिए। लेकिन वोट तो बहुत ज्यादा हो जाते है किसी के और उन का प्रतिनिधि एक भी नही पहुचता, या जिस अनुपात में पहुंचना चाहिए उस अनुपात में नही पहुचता। पहुचने चाहिए 20 तो पहुचता है एक क्यों कि सिम्पल मेजारिटी सिस्टम आप ने रखा है। तो सानुपातिक प्रतिनिधित्व की चुनाव पद्धति को अपनाया जाना चाहिए। तभी हम सही मानो में जनतांत्रिक सिद्धात को लागू कर सकेंगे और जनता को मतदाताओं को भी संतोष होगा कि हमारा भी प्रतिनिधि विधान सभाओं में और संसद के अंदर चला गया है। अभी वह समझते हैं कि हम ने वोट तो इतने हजार दिए लेकिन हमारा तो कोई भी प्रतिनिधि नहीं आया या आया भी तो बहुत कम आया जो अपनी आवाज ठीक से शासक दल तक पहुचा नही सकता है या उस का असर उन पर नहीं पड़ सकता है, यह वे महसूस करते हैं।

खास तौर से मैं कहूंगा कि जो वीकर सेक्शन के लोग हैं जिन को उठाने की बात सरकार बहुत करती है, बहुत अच्छी बात है। कमजोर वर्ग को उठाया जाना चाहिए, लेकिन कमजोर वर्ग को आज भी वोट नही देने दिया जाता। इस बार भी यू० पी० के एलेक्शन में यही हुआ। खुद हमारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव राजेश्वर राव ने खुला बयान दिया कि बांदा के बहुत सारे इलाके में हरिजनों को मतदान इस बार भी नहीं करने दिया गया। अब हरिजन भी, कमजोर वर्ग के लोग भी हाथ में लाठी लेकर और उस पर लाल झंडा लगा कर चलते हैं ताकि आप का जवाब वह दे सकें। जो भी गुंडागर्दी करेगा, जो भी वोट देने से रोकेगा उस के साथ वह स्वयं निपट लेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार की तरफ से व्यवस्था होनी चाहिए। वे बेचारे बहुत घबराते हैं . . . (व्यवधान) . . . मैं खत्म कर रहा हूं।

मैं यह कह रहा था कि कमजोर वर्गों के लोगों को आप मतदान-केन्द्र तक ले आने की पूरी व्यवस्था कीजिए। वे आज आ नहीं पाते। मुझे अपने क्षेत्र का अनुभव है और मैंने दूसरे संदर्भ में आपको बताया। वे कहते है कि हम आपको चंदा दे सकते हैं, एक सेर चावल दे सकते है पर हम वोट क्यों नहीं डाल सकते ? क्या दबाव है ? उनकी रक्षा की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। जहां वे काफी तादाद में हैं उनके लिए अलग बूथ अब बनने लगे हैं लेकिन पूरी व्यवस्था अलग बूथ की नही है आप मिला जुला बूथ बना देते है जहां शक्तिशाली और पैसे वाले लोग उनको मतदान करने आने नही देते। अगर वे लाइन में लगे भी रहते है तो उन्हें धक्का मार कर निकाल देते हैं और वे बेचारे चले जाते है। राजनीतिक तौर से वे इतने सजग तो हैं नहीं कि रामावतार शास्त्री के लिए लाठी ले कर लड़े। जो सजग हो जाते हैं वे लड़ते भी है। हरिजनों ने ऊंची जाति के लोगों को लाठी से कई जगह मार भगाया है और वोट दिया है। ऐसी भावना सभी बूथों पर पैदा होनी चाहिए।

ऐसा एक कानून बनना चाहिये जो इन सारी बातों का समावेश करता हो और जो वर्तमान कानून है उस में सुधार होना चाहिये ताकि सही मानो में स्वतंत्र, निष्पक्ष और कम खर्चीला, भ्रष्टाचार

रहित, सरकारी पदों के दुरुपयोग से रहित चुनाव हो सके। साम्प्रदायिकता, जातीयता, प्रान्तवाद और इस तरह की जो दूसरी बीमारियां है, उन से बचाव के लिए कानून बनना चाहिये। फिर भी जो लोग न मानें, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिये। तभी जनतंत्र को हम और ज्यादा सुदृढ़ और मजबूत बना सकेंगे और अपनी दूसरी समस्यायें जो देश के नवनिर्माण की हैं उनको हम हल करने की तरफ आगे बढ़ सकेंगे। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इन बातों को दिमाग में रख कर जवाब देते समय कुछ बातें जरूर कहेंगे।

श्री एम रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद): जो प्रस्ताव वाजपेयी जी ने रखा है उस के उद्देश्य से किसी को कोई इंकार नहीं। उन्होंने कहा कि चुनाव फ्री, फेयर और इम्पार्शल होने चाहिए। हमारी नीति 1952 से आज तक यही रही है। आज यह कांग्रेस को कोई नई चीज बताने की नहीं है। हमारे चुनाव की हिस्ट्री का एक वक्त देखिये कि 1952 में जब राजाजी ने मद्रास में गवर्नमेंट बनाई उस वक्त वह माइनारिटी गवर्नमेंट थी। शुरु से अगर कांग्रेस का किसी तरह से भी चुनाव जीतने का तरीका रहा होता तो इतनी अपोजीशन पार्टीज की इतनी मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स हर एक स्टेट में नहीं बनती। बंगाल में दो तीन बार बनी, केरल और यू० पी० आदि में बनी। हर पार्टी को पूरी पूरी आजादी चुनाव लड़ने की रही है। इसलिए आज किसी ने नए प्रस्ताव की जरूरत नहीं है।

यह कहा गया है कि वोटर को आने जाने से रोका जाता है। लेकिन आप देखें कि बड़े बड़े मिनिस्टरों को कोर्ट में जाने के बाद 6–6 साल तक इलैक्शन लड़ने से रोक दिया गया है। बड़े बड़े लोगों पर भी मुकदमे चले और वे डिसक्वालिफाई हुए। इस तरह से मौजूदा सिस्टम में कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है।

यह कहा गया कि जो अफसर है वे पार्शेलटी करते हैं। आप देख ही रहे हैं कि एन० जी० ओज० आजकल किस के साथ हैं। वे अपोजीशन के हाथों में खेल रहे हैं। थोड़ी बहुत मदद मिलने के अगर गुंजाइश है तो अपोजीशन को ही है। यू० पी० में इतना बड़ा इलैक्शन लड़ा गया। उस में कांग्रेस को मुश्किल से बेयर मैजोरिटी मिली है। यह कहा गया कि हम वोटर्ज और अफसरों पर दबाव डाल कर नाजायज काम करते हैं। अगर हम ऐसा करते तो हम लोग वहां बहुत बड़ा बहुमत ला सकते थे।

जहां तक ब्लैक मनी का सवाल है, इलैक्शन में वह किस को मिलती है? ब्लैक मनी की हिफाजत जो करते हैं उनको वे पैसे देते है। जो इसको खत्म करने के लिए रोजाना बिल और प्रस्ताव ला रहे हैं उनको वह पैसा कैसे मिलेगा? हमने प्रिवी पर्सिस को खत्म किया, रोजाना ब्लैक मनी पर रेड कर रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं मीसा के अन्तर्गत, तो वे लोग किस तरह कांग्रेस को पैसा दे सकते हैं? वाजपेयी जी मेरी कंस्टिट्युएंसी में गए थे मेरे इलैक्शन के थोड़ा पहले और तब उनको 51000 रुपये दिए गए। वे रुपये सौ आदमियों ने मिल कर पांच पांच सौ रुपये के हिसाब से दिए। मुझे 1 लाख 50 हजार वोट मिले और उनके कैंडीडेट को 25000 वोट मिले। आप देख लें 50000 रुपया मिला और 25000 वोट। इससे अंदाजा लगा सकते है कि ब्लैक मनी वाले किस की मदद कर रहे है। अभी जोशी जी मेरे क्षेत्र में भाषण देने गये थे, पता नहीं मेरे ही क्षेत्र मे क्यों जाते है। शायद मेरा क्षेत्र पैसे वाला इलाका है, चावल बहुत पैदा होता है, महाराष्ट्र मे बेच कर पैसा कमाते हैं, इस लिये यू० पी० इलैक्शन के वास्ते पैसा लेने गये होंगे। जब मैं अपने क्षेत्र मे जाऊंगा तब पूरा पता लगेगा कि इन को वहां से कितना पैसा मिला है।

17 Hours.

हमारे देश में रिटर्निंग आफिसर्ज जितने अच्छे है, शायद ही किसी देश में होंगे। उन्होंने छोटे-छोटे और बड़े-बड़े लोगों के नौमिनेशन पैपर्स को, यदि उन में कोई डिफेक्ट रहा है तो रिजेक्ट कर दिया है। यह कहना कि आफिशियल मैशीनरी वाले कांग्रेस वालों की सहायता करते हैं, गलत है, वे बहुत इम्पार्शियली काम करते हैं। लेकिन अगर कहीं कोई पार्शियेलिटी बरती जाती है तो उस आफिसर को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, हिन्दुस्तान मे हमारी डैमोक्रेसी मजबूती से नहीं चल सकती है।

हमारे देश में जितना मौड्रेशन है उस के लिये मैं बड़ा एमेज्ड हूं। इतने प्रोवोकेशन के बावजूद भी, जब कि प्राइम मिनिस्टर पर पत्थर फेंके जाते है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई। अब इस देश की अपोजीशन पार्टीज

के लिये मैं क्या कहूं—उन को इतना भी ख्याल नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर आफ इंडिया की क्या हैसियत है, इस तरह की कार्यवाही पूरे वर्ल्ड प्रैस में जाती है ....

श्री फूल चन्द वर्मा (उज्जैन) : प्राइम मिनिस्टर को तो ऐसे समय में त्यागपत्र दे देना चाहिए।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी: किसी भी देश में हिंसा की वृत्ति फैलाने के लिये बहुत लोगों की जरूरत नहीं होती है, 1 परसैन्ट या 5 परसैन्ट लोग भी इस काम के लिये काफी है। यू० पी० में इस काम के लिये 10 करोड़ जनता की जरूरत नहीं थी, 100 आदमी जनसंघ के या आर० एस० एस० के 100 मीटिंग्ज में पत्थर फैंक सकते थे।....

श्री फूल चन्द वर्मा : गलत। हम उन के मान सम्मान में पूरा विश्वास करते हैं। अगर हमारा उनके साथ मतभेद है तो राजनीतिक मतभेद है, हम प्रधान मंत्री के विरुद्ध नहीं हैं और आर० एस० एस० का पत्थर फैंकने से क्या संबंध है ?

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : अगर वे नहीं करते हैं तो मुझे खुशी है।

श्री फूल चन्द वर्मा : लेकिन आप गलत क्यों कहते है ?

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : मैं पूछना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर पर पत्थर किस ने फैंका—इस का जवाब आना चाहिए। वाजपेयी जी या सी० पी० आई० या सी० पी० आई० (एम०) किसी ने इस का कन्डेम्नेशन किया है ? जहां कहीं भी हम मीटिंग करें चाहे 10 आदमी आयें, हमें उस की परवाह नहीं है, लेकिन वहां आ कर हुल्लड़ क्यों मचाया जाता है ? क्या हमने कांग्रेस वालों की मीटिंग कहीं डिस्टर्ब की है ? मैं दक्षिण भारत की बात कह रहा हूं—हम लोग कभी किसी की मीटिंग डिस्टर्ब नहीं करते। कई जगह पर तो ऐसा हुआ है कि जनसंघ वालों ने पहले एड्रेस किया, बाद में मैंने एड्रेस किया, कभी डिस्टर्ब नहीं किया। हमारे लोग बाहर बैठे रहते थे, जैसे ही उन की मीटिंग खत्म होती थी, हम अपनी मीटिंग स्टार्ट करते थे। हम को डैमोक्रेटिक तरीके से चलना चाहिए, पत्थर फैंकना अच्छी बात नहीं है। हमारे देश में एक गोडसे हुए उसने महात्मा गांधी को गोली मार दी। महात्मा गांधी के साथ न केवल भारतवर्ष के लोग थे, बल्कि दुनिया के लोग थे, लेकिन उस के बावजूद भी एक आदमी ने उनको गोली का निशाना बनाया। इस लिये यह जो पोलिटीकल हिंसा बढ़ रही है, इसको रोकने के लिये सब पार्टियों को मिल कर काम करना चाहिए, तब फिर इतने खर्चे का सवाल भी पैदा नहीं होगा। इस समय अगर कोई मीटिंग होती है तो उस का पूरा बन्दोबस्त करना पड़ता है, प्राइम मिनिस्टर या दूसरे लीडर्स जाते हैं तो वहां पुलिसवालों का इंतजाम करना पड़ता है। अगर हर आदमी अपनी अपनी मीटिंग करे, उस में भाषण दे, ठीक तरह से इलैक्शन को चलने दे तो बहुत सारे खर्चे जो करने पड़ते हैं उन को रोका जा सकता है और इस से हमारा जनतंत्र भी मजबूत हो सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं बाजपेयी जी से अपील करता हूं कि अपने रेजोल्यूशन को वापिस ले ले।

*SHRI E. R. KRISHNAN (Salem): Mr. Chairman, Sir, on behalf of Dravida Munnetra Kazhagam, I rise to say a few words on the Resolution of my hon. friend, Shri Vajpayee, expressing his desire that free and fair elections should be held in a democratic country like ours, as he strongly believes that free and fair elections are the essential prerequisites for the success of democracy. I wholeheartedly extend my support to this Resolution containing this laudable objective.

It is common knowledge, Sir, that the Central Government have not taken any constructive steps so far to control the circulation of black money in our country. The main reason for the inaction of the Central Government in this direction is that without substantial assistance from black money the ruling party will not be able to hold the elections frequently and to contest the elections successfully. The Wanchoo Committee appointed by the Central Government has pointed out that black money in our country would be of

*The original speech was delivered in Tamil.

[Shri E. R. Krishnan].

the order of Rs. 5000 crores. The Central Government may tolerate the spiralling price rise in essential commodities. Even then they will not take appropriate steps to control black money because it is required for elections.

Some three months before the Tamil Nadu Legislative Assembly passed a Resolution unanimously—you know that there are Opposition Parties in the Tamil Nadu Assembly—demanding that the power to control and confiscate black money should be vested with the State Government. Yet The Central Government have not yet given their approval to this unanimous Resolution passed by the Tamil Nadu Legislative Assembly.

It is accepted by all in the country that the account of election expenses is bogus and does not reflect the actual expenses. Our Prime Minister has submitted her election expenditure in Rai Bareilly constituency to the Election Commission. Her election expenditure is just Rs. 12,000. Even to come round a parliamentary constituency the petrol bill alone will be coming to Rs. 12,000/-. From this it is obvious that the election expenses as submitted to the Election Commission are all false and incorrect.

I will give one or two political and administrative corrupt practices employed in the recent U.P. Elections by the ruling party. We all know that during one month before the Elections, the Prime Minister laid foundation stones of 15 gignatic projects at a cost of Rs. 400 crores. In a place where there is no river, the foundation stone was laid for a bridge—this news appeared in all the newspapers of the country.

Announce any number of projects; adopt any dubious means to get the votes of the people—this is the main objective of the ruling party. All the projects for which foundation-stones were laid by the Prime Minister do not find a place in the Fifth Five Year Plan of the U.P. State. 75,000 workers in Faridabad, Haryana State may lose their livelihood for want of electric power. Yet, the States of Punjab, Haryana and Delhi must supply all the electric power to the U.P. because elections are going to be held there. You know, Sir, that 20 miles from Delhi there is the town of Ghaziabad, where I happened to go last month. I found to my great surprise that sugar was being sold there at Rs. 3 a kilo, while in Delhi it was Rs. 4.50 a kilo. Give all such concessions and get the votes of the people—this is the motto of the ruling party.

Similarly, the price of sugarcane was raised. We all felt that after all the sugarcane cultivators would be getting remunerative prices. But, after a few days the price of sugar was also raised. Without raising the price of sugar, the Ruling Party would not be able to get crores of rupees from the sugar mill owners for the elections. In one month, the U.P. Government employees were given three instalments of increase in their D.A.! The U.P. Government employees were agitating for many years; but they were given in one month what they were asking for during the past many years.

You know, Sir, that the people living in Hill areas of U.P. do not have proper shelter over their reads, do not get enough clothing to cover themselves from sun and showers and do not get two square meals a day. But, the U.P. Chief Minister, Shri Bahuguna, has assured them a University in the Hill areas. In Faizabad, a small town of U.P., the Chief Minister, Shri Bahuguna would establish a University. In each District, a College would be established—this is the election promise of the Chief Minister. In total, 127 Ministers—Central Ministers, U.P. State Ministers, neighbouring States' Chief Ministers and Ministers—have toured U.P. during the election month for the sake of ruling party's propaganda. All their expenditure—it is reported in the Press—seems to have been met from the public exchequer.

Four months before the elections, the President's rule in U.P. was prorogued and a popular Minister under Shri Bahaguna was installed there. Did the U.P. Assem-

bly meet even for once after the popular Minister was installed in U.P.? No. Then, what for the President's rule was prorogued there and the popular Ministry was set up? Here, it is necessary for me to refer to what happened in Pondicherry. For five years there was D.M.K. Government in Pondicherry. In Pondicherry, for five years there was the administration of popularly elected D.M.K. Ministry. Three months before, the Pondicherry Assembly met for the last time in which all the 30 Members participated in the valedicatory discussion. After that, two D.M.K. Ministers resigned from the Ministry and defected to an Opposition Party. Technically, the D.M.K. Government could have continued for the remaining three months also. But, the D.M.K. Government did not do so It also resigned. The Dravida Munnetra Kazhgam is wedded to democratical ideals and is pledged to foster democracy in the State The D.M.K. wanted to ensure free and fair elections in the State. The resignation of Farooq Marakkayar's D.M.K. Ministry goes to show the D.M.K.'s unassailable faith in democracy and the necessity to establish sound and noble democratic conventions in the country. But, in U.P. the ruling party at the Centre has got different views about democracy. Just before the elections, the President's rule was prorogued. The popular Ministry was installed, not for the purpose of convening the Assembly, but for the purpose of utilising the vast administrative machinery and power in the coming elections. I have given this comparison to show how the premier political party in our country, the oldest political party in our country, the political party which brags that it has achieved Independence for the country, is interested in perpetuating its hold on the masses and in winning the elections by hook or crook.

Recently, a circular was issued to all the State Governments in the country stating that whenever the Prime Minister visited a State for election propaganda purposes, the expenditure in that connection should be borne by the State Government concerned. On 17-2-1974 the Prime Minister visited Pondicherry and the expenses on her visit to Pondicherry for election propaganda purposes came to Rs. 10 lakhs. A small state like Pondicherry had to bear such a heavy expenditure of Rs. 10 lakhs incurred on Prime Minister's election tour.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY: What is the expenditure?

SHRI E. R. KRISHNAN: 10 lakhs!

SHRI M. RAM GOPAL REDDY: On what items this amount was spent?

SHRI E. R. KRISHNAN: Her election tour expenses. When the Prime Minister was doubtful in 1971 about getting majority in Lok Sabha, she had electoral alliance with the D.M.K. and got 9 Congress Members elected to Lok Sabha from Tamil Nadu. She did not put a single Congress candidate for the Tamil Nadu Assembly. Some months before when a Press Correspondent asked the Prime Minister whether there was any likelihood of Shri Kamraj joining her Congress, she replied: "what is going to do at this age by joining the Congress?" But, now she had no compunction in joining hands with the very same leader, Shri Kamaraj, in Pondicherry| Indira Congress and Kamaraj Congress are one in Pondicherry. But, in U.P. they are fighting against each other. In Coimbatore, they are one. But in Orissa they are fighting against each other. In Tamil Nadu, according to Shri C. Subramaniam, who was elected to Lok Sabha with the support of D.M.K., they are one. But in Madhya Pradesh they are poles apart. It is really regrettable that an all-India Party like the Congress, having majority in the Parliament, should not have any principle or policy. From State to State, from town to town, from area to area, the policy and the principle of the premier political party in the country differs. There is no uniform policy even in one State. In U.P. the Congress contested only 403 seats and gave away 22 seats to its ally, the C.P.I. Did the C.P.I. rest content with these 22 seats? No. The C.P.I. put up candidates against the Congress in many other constituencies, besides

[Shri E. R. Krishnan].

the 22 allotted to it. The Congress Party tolerated this breach of the alliance.

The Tamil Nadu occupies the first place in the export of raw hides and shinks. Last year a ban was imposed on the export of raw hides and skins on the ground that finished leather products would get more foreign exchange for the country. But, just before U.P. Elections, this ban was litted. Many differing views are being expressed by the public on this action of the Central Government. This shows that even the economic interests of the country occupy a secondary place when elections are to be held.

The Wanchoo Committee has made certain recommendations for the conduct of free and fair elections in the country, which Shri Vajpayee wants the Government to implement. In his capacity as the leader of the Jan Sangh Party, he does not want the view-points of his party to be implemented by the Government. Similarly, the Chief Election Commissioner in his Report has pointed out the necessity for amending the Representation of Peoples' Act. But the Central Government have not done anything in this regard. Last week in this House, the Governmei brought an amendment to the President's and Vice-President's Election law. What prevents the Government from bringing forward an amending bill for the Representation of Peoples Act ?

Coming now to All India Radio, I will give-one or two instances to show how the All India Radio has shown scant regard for healthy democratic conventions. All India Radio was not interested in announcing the success of ruling party's candidates in the Elections. On the other hand, All India Radio gave great importance to the set-backs of Opposition Parties in the Elections.

"C. B. Gupta is trailing behind all the candidates."

"Singh Deo in Orissa has been defeated."

"The D.M.K. in Pondicherry has been routed."

"The D.M.K. candidates are trailing behind."

Such announcements only have got first preference with All India Radio, and not the success of ruling party candidates. This was the respect and regard shown to political parties in the country by the All India Radio. All India Radio did not announce the defeat of the U.P. Minister, Shri Vikal, in the Elections. It did not also say who defeated him. In the recent President's Address debate, the Opposition Leaders like Shri Morarji Desai, Shri Vajpayee participated. But All India Radio did not care to mention by name any of the Opposition leaders. Is this propoer ? Are the Opposition party leaders not the citizens of this country? Are the Opposition Parties not necessary for the success of democracy in our country ? The Wanchoo Committee in its report has pointed out that after the ban imposed by the Central Government on the donation by companies to political parties, the circulation of black money has taken deeper roots in the country. The five General Elections conducted in this country have proved beyond doubt that the ruling party cannot survive without the support of black money.

The Election Commission has suggested that the limit of Rs. 35,000 for expenditure in a parliamentary constituency should be raised at least to Rs. 50,000 in view of the prevailing price rise. I request that the Government should consider this favourably. Similarly, in its Report on 1971 Elections, the Commission has stated that 2100 complaints were received at the time of elections and it was not possible for the Commission to look into all of them at that time. The Government must look into this problem and do something to remedy the situation.

The ruling party swears by the establishment of secular and casteless society in the country. But, I feel that the ruling

party is the breeding ground for the perpetuation of casteism and communalism in the country. I say this because the ruling party selects candidates for elections on the basis of caste, community etc. The Election Commission has also referred to this.

In conclusion, I would quote what has been stated by the Chief Election Commission on page 198 of his Report on 1971 Flections :

> "But, how can we expect that elections will be absolutely and totally corruption-free, when the whole country in every sphere and department is plunged in the ocean of corruption. Remove corruption in general and corruption in election will be a thing of the past."

The Chief Election Commission has acknowledged that there is widespread corruption in Flections. But he is not able to do anything because the Election Commission is just a part of the Central Government's administrative set-up. The Election Commission must really become an independent and autonomous body equipped with even judicial powers. Then only free and fair elections will become possible in this country.

With these words, I conclude my speech supporting Shri Vajpayee's Resolution.

SHRI DINESH CHANDRA GOSWAMI (Gauhati) : From the Opposition side we have heard Shri Vajpayee from the Jan Sangh, then our CPM and CPI friends and lastly our friend from the DMK. I can spot the sence of frustration and anger in their speeches. In fact, Mr. Vajpayee went on to say that in the present state of the election machinery and election atmosphere he was feeling helpless that the ruling party could never be displaced. I can understand their frustration because the UP election result has totally rejected Mr. Vajpayee's ambition of getting 229 seats in UP. I do not know, but there was a rumour also that he was thinking or his followers were thinking of having Mr. Vajpayee as the Chief Minister of UP.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : What about Mr. Bahuguna's 350 ?

SHRI DINESH CHANDRA GOSWAMI : I can see the feeling of helplessness and anger in the speech of my CPM friend because at least in one matter they have helped the Government that their offspring has never crossed the limit of two in most of the States. I can see the feeling of anger and anguish of my DMK friend, because the whole existence of his party is in great jeopardy. Therefore, when these friends have attacked the election machinery today from a particular angle, I do not subscribe to that view. It is not that I am saying that the election machinery today is completely free from corruption. I do admit that there are many things which need to be cleaned up and to that extent I support Mr. Vajpayee's contention.

My hon. friend from the DMK had said that Congress had not principle on the ground that they had made an alliance with the DMK in 1971 but now they had made an alliance with the CPI and Congress (O). I cannot understand this argument that in 1971 when we made an alliance with the DMK we had principles, but when we made an alliance with not the DMK but with other parties like CPI we had no principle. If we have no principle, then we had no principle in 1971 when we made an alliance with the DMK, and on the same reasoning, his party also had no principle, because if in an alliance one party has no principle, the other party obviously also has no principle of its own. Therefore, the arguments that have been advanced here are absolutely void of any reason.

If we look at the present elections and the results thereof, it would be noted that the people have given a very correct verdict of their own, and the more the Opposition continue to say that the election is rigged. I think it will hurt them more because thereby they hurt the sentiments of the people. It is not that the Congress or the parties which have been put into

[Shri Dinesh Chandra Goswami]

power have come by dubious means or because the election was a rigged one, but it is because the people have expressed their views in unequivocal manner in favour of these parties.

From the results of the UP elections, two fundamental things have come up in order to show that the arguments that the elections are rigged are not valid. If we have lost in Manipur in the elections, that shows that the election is not rigged, because if the elections were rigged, we could have won in Manipur, because if we are capable of rigging the elections in UP or Orissa we can also rig in the other States. Therefore, let not this kind of complaint be made.

The elections in UP and Orissa have shown certain trends, which reflect the opinion of the people. The trend in UP is that the Independents have completely been made to vanish from the election scene, because the people have rejected the Independents. Further, the Congress (O) has been completely trounced, and a person like Mr. C. B. Gupta lost his security deposit. It means that there has been to a certain extent the polarisation of forces and the rightist forces have been rejected in UP.

Look at Orissa. What has happened in regard to the voting in Orissa today ? Those persons who really brought about the fall of the Government there by crossing floor have been totally rejected by the people. Take the case of Shri Nilmony Routray (*Interruptions*). I am not saying that this has happened universally. What I am saying is that these are the trends. These trends indicate that the people of this country, by and large, have been conscious and they have given a conscious vote. Even with our shortcomings, if we have come out successful, it speaks very sadly of the Opposition. People have voted us to power because they are satisfied with our policies and also because the Opposition has never been able to have a positive approach, has never been able to place a positive programme before the people (*Interruptions*). Your shouting in the House will not do. By shouting here, you will not be able to catch votes.

If the Opposition really want to strengthen democracy in this country, if the Opposition parties are interested in democracy, I feel they should come out with a positive programme and a policy of their own, because that will also strengthen the ruling party; it will also strengthen democracy. I do feel that if democracy collapses, not only Opposition will collapse but all of us will collapse.

Therefore, as a lover of democracy, I do want that democracy should be strengthened. Democracy can be strengthened with a strong Opposition with a positive programme. But merely saying that elections have been rigged that we have won because the elections have been rigged will not do. There should be a searching of hearts on this side of the House and on the other side

Coming to the Resolution, some irrelevant factors have been introduced into it. One is the use of helicopter by the Prime Minister. This has been debated in this House. It has also gone to courts of law. After all, the courts of law have also said that the Prime Minister of the country is a person who must be given adequate security. This is so because there are not only forces inside the country, but there are forces outside the country also who will be interested in harming the Prime Minister. Therefore, if the Prime Minister is given a Defence 'plane or helicopter, I do not think the heavens fall thereby'. Also that really makes no change in the people's verdict. There are cases where even though the Prime Minister has gone in a helicopter, we have lost the election. It is not that we have won because the Prime Minister went there in a helicopter. Helicopter cannot fetch us votes. After all, the people have voted for us—it is not for the helicopter—but because the Prime Minister is the only leader in the country who has the image of an all-India leader,

who has placed before the people a positive programme.

Shri Vajpayee referred to election expenses and said that money was playing a very bad role. I entirely agree. But to say that because of black money this is happening or that election expenses are absolutely responsible for black money or the present state of affairs is, I think, to indulge in an oversimplification of facts. There are many other factors like the administrative machinery, the administrative system. These should not be overlooked.

One of the suggestions he has made is that like in some western countries, political parties should be financed. This is undoubtedly a suggestion which we should all very seriously ponder over. But what I am feeling is, firstly, it will be difficult in a country where so many political parties are there. And by this, will you not permit the Independents to come into the political platform to contest ? Obviously, a decision on policies shall have to be taken If we decide only to finance political parties, obviously the election will be open for political parties only and not for Independents. Here, I would obviously like to hear Mr. Mavalankar.

The second most difficult thing in this country is that really, in many cases, the concept of a political party has not grown here. If we look to the political developments of this country, we will find that here parties have not grown by themselves. Parties are grown out of individuals. It is not that the individuals have become products of parties as in other countries. In other countries, individuals are the products of parties. Here, the parties have become the products of individuals. There is a clash between Shri Madhu Dandavate and Shri Raj Narain; immediately two parties come up. Shri Vajpayee and Shri Madhok do not see eye to eye; two parties come up. Therefore, it is the product of individuals, and unless we can—

श्री ओंकार लाल बेरवा : श्री मोरारजी देसाई और प्रधान मंत्री के बीच झगड़ा हुआ और दो दल बन गये ।

SHRI DINESH CHANDRA GOSWAMI : Please at least try to understand what I am saying. What I am saying is this. (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN : How many times have I requested you not to interrupt ? This is contrary even to the rules. You can say whatever you want when your turn comes, but please do not interrupt. Don't repeat this again.

श्री ओंकार लाल बेरवा : अगर वह हमारे लिये कह सकते है, तो क्या हम उन के लिए नही कह सकते है ? क्या श्री मोरारजी देसाई और प्रधान मंत्री के बीच झगड़ा नहीं हुआ है ?

SHRI DINESH CHANDRA GOSWAMI : May be. But we do contend that the defeat of 1969 elections was not because of individuals but because of certain basic policies. You may differ with me. Mr. Vajpayee may contend that because of policy differences—

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति महोदय, क्या मेरा और श्री मधोक का झगड़ा व्यक्तिगत है और प्रधान मंत्री तथा श्री मोरारजी देसाई का झगड़ा सिद्धान्त का है ?

SHRI DINESH CHANDRA GOSWAMI : I am very glad when Shri Vajpayee has contended that Mr. Madhok's party is a party with certain principles, with basic differences with Shri Vajpayee's party. I am very happy to know about it. If you concede that, I am really happy.

MR. CHAIRMAN : He concedes. (*Interruptions*).

SHRI DINESH CHANDRA GOSWAMI : I am conceding. So, a political perspective must grow in this country.

The second most difficult thing is this. Supposing the political parties are given finance. Shall we be able to prevent spending of money by individual candidates apart from the finance that is given by

[Shri Dinesh Chandra Goswami]

the political party ? After all, there is a law that you cannot spend more than Rs. 35,000. But everybody is spending more than that. Supposing the Congress is given Rs. 20,000 and the Jan Sangh is given Rs. 20,000, shall there be any machinery by which we will be able to limit this expenditure to Rs. 20,000 alone and not more ? Unless you can bring about a machinery—

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : The parties should give their accounts.

SHRI DINESH CHANDRA GOSWAMI : Suppose, talking as a Congress candidate, from the party's fund I get Rs. 10,000. Unless there is a machinery by which it is ensured that a candidate cannot spend more than what is allowed, the entire thing will be frustrated. But, at the present moment, there is no machinery because, in spite of the law that you cannot spend more than Rs. 35,000, it is an open secret that they frustrate the election law; by devious means they do spend more than Rs. 35,000. And it is very easy to frustrate the law because if a friend gives the money, or gives the car, then you cannot get within the purview of the election law.

Therefore, this is a thing which does require very serious consideration. I have my own doubts whether it will really help in the solution of the case unless the entire machinery to a great extent is changed to see that the law is implemented but in the present state of affairs I do not feel that we will be able to do it.

Some of the other suggestions of Shri Vajpayee are for equal time over the radio and all that. There again I feel that unless the political parties come to some agreed consensus, it will be very difficult. The only setback has been the lack of an agreed consensus I do wish that the major political parties come to some consensus.

In conclusion, I feel that if we want really to make democracy successful, each political party shall have to approach the election with a sense of responsibility and with a sense of duty. It is not that the Congress plays up the forces of casteism. Do not blame us, because I feel that the Congress is the only political party which plays down casteism as far as practicable. Really, one of the ways in which probably we can really face this problem is this. I have a suggestion in my mind. When you contest an election to a seat in the State Assembly or Parliament, the names of the candidates need not be printed in the ballot paper. If Mr. Vajpayee's contention is accepted that elections should be fought on the basis of political parties, and not independents—with all apology to Mr. Mavalankar who will, I hope, join a political party and I am sure it will be this side of the House—we need not print the names of any candidate We will simply say : the Congress, the Jan Sangh and the BKD. The electorate will decide whether to accept the Congress, the Jan Sangh or the BKD. In that case caste and communal considerations will not come to play It will be up to the Congress or any other party which wins that constituency to say : we are giving such and such person as our candidate in this constituency. That is a suggestion by which we can diminish to some extent caste and communal considerations But it has its own limitations I admit that unless caste and communal considerations are removed—they erupt at the time of every election—the future of the country is gloomy I endorse the spirit with which Mr. Vajpayee has brought this resolution and I do hope that the Law Ministry will give serious thought to this matter and some fruitful result will come out of this.

MR CHAIRMAN : Two hours' time was allotted for this resolution and that time is over There are about 8 or 9 persons more who want to speak.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI K. RAGHU RAMAIAH): I suggest that we may extend the time by one hour.

MR. CHAIRMAN : The time is extended by one hour. There is only half an hour left today; so this debate will continue the next time.

SHRI P. G. MAVALANKAR (Ahmedabad) : It is an interesting and happy coincidence that this discussion on Mr. Atal Bihari Vajpayee's resolution should take place on the morrow of the election results from UP, Orissa, Pondicherry and Manipur. This discussion is therefore not only vital but also topical. I recall Shri Vajpayee trying hectically to move this resolution during the last session and getting some time to elaborate on his ideas about free and fair elections so that they could have some impact on elections in U.P. and other States, not only for one party but for all parties. But I could see the manner in which the earlier discussion on that occasion was prolonged. There was perhaps a desire to postpone this discussion on Shri Vajpayee's resolution until after the elections in U.P. and other places were over. I wonder if that was being fair to Shri Vajpayee. The Prime Minister mentioned this morning that elections are only the method; what is more important is the principle or the programme of action. I hope that this discussion on free and fair election will be useful in creating a healthy atmosphere. We all know that the general election is a kind of peaceful revolution... *(Interruptions)*

17.39 hrs.

[SHRI JAGANNATHRAO JOSHI *in the Chair.*]

May I join my friend on the right, the Members of the Jan Sangh, who are congratulating you; I am sure the whole House Joins me in greeting you on your occupying the Chair. I was saying that it was through the ballot box that we keep alive the ordinary man's faith in being able to change the Government or the rulers whenever he likes. In any election there is an opportunity for the people not only to reject certain individuals and certain parties but also to accept certain individuals and certain parties. I want to say at the outset that I am not going to discuss Shri Vajpayee's Resolution in the context of the current politics only and in the context of the very recent elections, to which I made a reference earlier. It is natural for members belonging to the different political parties to refer again and again to this or that controversial political hot issue and pin-point discussion on that. If you will permit me, Mr. Chairman, Sir, I would like to lift this discussion to a little different plane; I do not say a higher plane but a different plane.

I would look at the problem as a challenge to all of us, whether we belong to the political parties or not. I want to suggest that while talking about free and fair elections let us not be very impatient. After all, we have had only five general elections and we had only 25 years of our new Republic and new democracy. I should say that by and large the experience of the last five general elections tell us that the elections have been conducted fairly freely and fairly fairly. Now, it is not right for the opposition parties to say that the elections are rigged when they lose and say that the elections are not rigged when in the same elections their own candidates win in some areas. You cannot have it both ways. If at a particular time the elections are free and fair or not so free and fair, the advantages or disadvantages must go to all parties and candidates in an almost equal way.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Not necessarily.

SHRI P. G. MAVALANKAR : I am glad Shri Vajpayee Ji interrupted me. Of course, it is not necessarily so in every case. But you cannot say that because you lost in a particular constituency, therefore, the election in that area was rigged and in another constituency you won on the basis of your strength. That would be stretching the argument too far.

Having said that the elections in this country have been free and fair by and large, I want to emphasize the phrase "by

[Shri P. G. Mavalankar]

and large." Even now, even in the year 1974, there is no country in the world wherein we can say that the elections are completely free and fair. Even in the best of democracies some unfairness and some kind of unfree methods and tactics do take place. It is a process in which after you gain some experience, through the trial and error method you go on eliminating what you consider as unfair practices and go on concentrating and strengthening what you consider as good practices.

My complaint is that even on the basis of the limited experience that we have gained over the last 25 years, we in this country have not, unfortunately, tried to strengthen the experience which tells us that this is the way the elections can be held freely and fairly and these are the evil ways which we have to discard. I want to suggest that just as no country can say that it has got completely free and fair elections, similarly, no political can say, not only in this country but anywhere in the world, that it has not indulged in unfair practices. So, to say that only the ruling party is having all the corruption, bribery and other unethical practices is an exaggeration and a misstatement. While I do not want to be uncharitable to any party—I believe in being charitable to all—I want to say that if some of the opposition parties come to power either in one or the other of the States or in the whole Union I do not know whether they would not also copy, and copy with a vengeance, what the ruling party is doing today. Therefore, it is no use saying that except the ruling party, all the other parties are good and innocent. Perhaps, the opposition parties have not had an opportunity of being bad or corrupt.

I want to suggest that in a democracy, elections are of course important. But if we understand that wherever there is a democracy, there must be elections, meaning that there must be a choice between two clear-cut alternatives, if not more, you cannot, therefore, say that the converse is true, that the reverse is true, that is, wherever there are elections, there is of necessity a democracy. Therefore, I want to suggest that if you want free and fair elections to continue or to be strengthened, then we must not look at the elections as an end in themselves but we must look at them as a means in themselves.

You take the countries like the United Kingdom, the United States of America and other Western democracies of Europe. You will find that they also have been able to achieve a fairly reasonable target of free and fair elections after decades of practice. What they could achieve after decades was possible because they went on eliminating what they found by experience to be unworkable, undesirable and corrupt practices in the election procedures. That we are not doing. That is my charge.

When I make a reference to these countries, incidentally, I should have said in the very beginning that the discussion on Mr. Vajpayee's Resolution is also topical because in another country also, in the United Kingdom—one of the oldest democracies of the world,—the elections have just been held. We know how fair and free these elections in UK, compared to other democracies, have been.

Apart from providing the kind of machinery which Mr. Vajpayee wants, apart from the provision of a good and sound election machinery, an independent and impartial Election Commission, what is equally necessary, if not more necessary, are some of the institutions like public opinion, free press, enlightened universities and well-established conventions of holding democratic elections and also, of course, citizenship consciousness and alertness. We know that eternal vigilance is the price of liberty.

Sir, as you have rightly rung the bell, I would now like to comment briefly on some of the points which are contained in the Resolution moved by Mr. Vajpayee. He has talked about growing influence of money power. I entirely agree with him. I think, the whole House will agree with him. It has become impossible even for a rich man to fight elections, to succeed in elections, what to talk of a poor man or a middle-

class man. This is not a phenomenon particularly relating to Indian conditions. Even in countries like America where the people are fairly rich, where the parties are very resourceful, where the candidates are very rich, they find that money becomes a fantastic factor in fighting elections. Therefore, if you want to have free and fair elections, all political parties, all candidates, certainly Independents also, could and should see to it that they are not guilty of spending more than what is permitted by law. If we believe that this must be the practice, then we must start it with ourselves.

About Mr. Vajpayee's charge regarding the abuse of official machinery, I agree with him. There are a lot of good conventions established in U.K. Why not establish those conventions here also? My hon friend, Mr. Goswami, referred to the Prime Minister using helicopters and other aircraft, and said he saw no harm or wrong, in such use. I am not referring to this or that individual or to the present Prime Minister as such. But, all that I want to say is that it is not a fair practice. Because the Prime Minister or the Ministers or the Chief Ministers are able to use the vehicles or the aircraft or other things which are at the disposal of the State machinery, they help to hypnotise the voters and create a wrong climate.

In England, I remember to have seen it myself, in October 1951, Lord Atlee—at that time, Mr. Atlee—was going in a private car, Mr. Atlee driving a private car, and both of them were going on an election campaign just 10 to 15 days before the elections.

Atlee was still a care-taker Prime Minister. But, he was not using even an official motor car, much less an aircraft.

About the election grants, I agree with Shri Goswami as to why should it be given to the parties? Why not for Independents also? But, instead of giving grants to political parties, I would say firstly that let the Election Commission do two things. Let the Election Commission send the information card to every voter showing the voting number and the polling booth where he has to go.

Secondly, let the Election Commission make it possible for every candidate to send one free communication by post to all his voters. If that happens, a good part of the expenses will automatically be curtailed.

I agree with Shri Vajpayee that the Election Commission members should be increased by having more than one Member. I also agree that the age of adult franchise must be reduced from 21 to 18.

MR. CHAIRMAN: You will please agree with me to close your speech.

SHRI P. G. MAVALANKAR: Yes. Only I want to say this in conclusion. A beginning has to be made, especially, by those parties and individuals who believe in free and fair elections. Only the politically educated and enlightened persons could do this. About the relationship between ethics and politics, very rightly so, the German philosopher, Kant says: "True politics cannot take a single step ahead before it has first paid homage to morals". Therefore, those of us who believe in politics coupled with ethics, for us then, let us carve out our own code of conduct. For those who are convinced, they must themselves provide an example. Thus, I am sure, we can do something by way of providing a free and fair election. Since you want me to conclude, Sir, I would only refer to one book without reading one or two quotations from it. This is an interesting book which has just been published, in December, 1973, by one Shri R. P. Bhalla. The title of the book is 'Elections in India'. The last Chapter—Conclusion—gives us a very interesting summary and the author's observations on this important subject.

With these words, I conclude by expressing my apology for having drawn on your generosity.

SHRI SAMAR GUHA (Contai): Mr. Chairman, Sir, freedom, fairness and peace are the three guiding principles for any

[Shri Samar Guha].

democratic election. But, the way these principles are getting eroded, I am afraid, an apprehension is developing increasingly that the future democracy in India is getting darker. Although Gujarat has shown us the way, perhaps, it is a new hope for us and for the Opposition to see to it that the democracy should be safe in India. I am one of those who condemned the happenings in Gujarat. This is the only means by which the Indian democracy can be saved and that too by the Gandhian means.

I have not much to say since the problems have already been elaborated by my friends, Shri Vajpayee and others. But, the most difficult part of having a democratic election in our country is this that the Central Government and the State Governments are not only in control of political power but they are also in control of the economic power—the most. Now, coupling these two powers—the political power and the economic power—and the way the government is abusing or misusing its authority by using the administration for influencing in the election and also for raising funds, I do not know, whether there is any future for any honest person, a person with integrity, a person committed to moral values, in having a hope in future to contest the election. Not only that. In our return, in most of the cases, unfortunately, it happens, wrong returns are given. But, it would, even, be difficult in future to prepare a wrong return because a fabulous amount is now being spent in the State elections. I do not want to go into details. My friend was saying so eloquently about the use of helicopters by our Prime Minister. Shri Ram Gopal Reddy was telling us—he is not here at the moment—that people were throwing stones at our Prime Minister. That was perhaps out of anger they might have done. About this he was talking so loudly. But, I do not know what will be the opinion of the international world believing in democratic values ? The Prime Minister, just a month before, in a State only, went for performing or doing the opening ceremony—galore—of project which has not yet been finalised or approved by the Planning Commission. Sir, what will be the reaction of the international world on abusing of such political and economic power, I don't know. I don't want to go into the details.

Sir, peace is one of the conditions for a democratic election. Recently my experience in Gaighata byelection is really horrible. I have sent a telegram to the President of India and to the Election Commission, to the hon. Speaker and the Prime Minister and to the leaders of all opposition parties. This telegram was not allowed to be read on the floor of the House. So I take this opportunity to read it This is what I said in the telegram. I quote :

> "All polling stations of Gaighata by-election completely overpowered by Congress terrorists. Socialist candidate threatened at the point of revolver. While capturing polling booths by Congress gangs armed with revolvers, bombs, daggers, threatened polling officers, polling agents and voters in general Ballot papers forcibly seized and fraudulently cast either before polling started or within 3 hours. Police blatantly sided with Congress armed terrorists. All norms of democratic elections totally violated. Socialist party withdrew its candidature in protest. Congress Organisation candidate of Belgachia withdrew under similar circumstances. Declare election void and hold immediate inquiry directly."

I am going to see the President and I hope to see the Election Commissioner also.

Sir, my experience just two days before was this : When I went there to address election meetings, I found that the atmosphere was full of terror and tension. The mood of the people was like that. Just a few days before the Chief Minister of West Bengal addressed some meetings. It is not for me to say these, it is an indication of the people's anger. What happened ? My meetings were of larger volume and they continued late into the night, peacefully, very orderly. But as soon as I finished my meeting on the 21st, there was a rush in the street in Calcutta and do you know

what happened? A report came that there was a bomb that was being made, being prepared, in the Congress election office, as a result of which one Congress worker died instantaneously and one was injured. The people rushed there and requested the police to arrest them. Then we approached the police. To our horror again, instead of arresting those, these people who made the complaints were arrested. Next day, I went to address another meeting. I was surprised to find this situation The earlier day thousands of people came there. On the next day not even 20 people were there in the maidan. Yet I continued. After that, about 20 or 30 people came, but they told me frankly: 'We are absolutely under terror, it is not possible for us to attend.' Two days before the election truck-loads and jeep-loads of terrorists were brought from Calcutta. They were parading in batches of 25 showing their revolvers, bombs and lethal armaments and the like, terrorising people, don't try to vote against Congress. Just on the eve of the day before the election, or, on the election day, that is on the 24th, at about 1 A.M. at night, what happened was, gangs of terrorists entered into a number of places where the polling officers were staying, they seized the ballot papers, they sealed the ballot papers, they marked the ballot papers, they fraudulently cast these ballot papers in the ballot-box, and sealed it before the election started. In the morning it happened that in a number of booths, when the people went to cast their votes, they were informed that already the polling was completed. I will show you two photostat copies.

At a number of polling stations those armed gangs were telling people : 'Already 80 to 95 percent of votes were cast ; you are not the real voter ; why are you going there? Votes have already been cast.

18 hrs.

I have already stated that a candidate of the socialist party was threatened at the point of a revolver and many others were threatened at the point of revolvers when they were in the jeep load throughout. They were going from booth to booth ; they seized the ballot boxes at night ; even in the morning, just after the beginning of the polling, within an hour or two, a number of polling booths were captured. The polling agents and other persons were either not allowed to enter into the polling booths or they were threatened and ousted from the polling stations. As it happens, they threatened the polling officers and they seized the ballot papers and they then cast the votes after marking them and then sealed them. They said that the polling had been completed but, actually, there was no voting at 11 A.M. I shall give you two interesting papers. This is the one signed by the Polling Officer himself. I read :

"I, the undersigned, P.O. Party No. 99/80 of Polling Station, state that many persons came to the booth at night on 23-2-74 and forced me to deliver the ballot papers. They also marked the ballot papers from 077041-077439. Total 499 ballots. Voters complained rigging as they could not cast their votes.

Sd/- Ajot Kumar Mandal,
2nd Polling Officer.

Sd/- Ranjit Kumar Mandal, 1st Polling Officer.

Sd/- Swapan Kumar Chakarvarty."

There is another thing.

MR. CHAIRMAN : You will please conclude.

SHRI SAMAR GUHA : I shall continue next time after a minute. This is signed by the A.D.M. I hope the Government will take a serious note of this matter to institute an inquiry. Let there be one instance that the election is declared as void. Elections should be held again. In all the eleven booths, even if they order a re-election, that will not satisfy us at all because, there was no election at all since most of the booths were captured and fraudulently, the votes were cast.

[Shri Samar Guha]

Therefore, I request the Government, at least from the side of the Congress, to approach the Election Commissioner to declare the election as void and he may order a fresh election.

Sir, I shall continue next time.

MR. CHAIRMAN : The House stands adjourned to re-assemble on Monday, the 4th March, 1974 at 11 A.M.

18.04 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, March 4, 1974/Phalguna 13, 1895 (Saka).

MGIPRRND—67 LSS/73—Ist NIGHT—2-5-74—490